दैनिक
साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -94 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, गुरूवार, 2 अप्रैल 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

चंडीगढ़ ब्लास्ट : खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह ने किया बीजेपी दफ्तर के बाहर बम ब्लास्ट, पोस्ट कर ली जिम्मेदारी

• नई दिल्ली, एजेंसी

चंडीगढ़ | भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए बम धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर ने लेने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में हुए ग्रेनेड हमले के पीछे वही है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि भारतीय सिस्टम चाहे पंजाब के सिख युवाओं के खिलाफ कितने भी कदम उठा ले, इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा गया कि खालसा पंथ उचित प्रतिक्रिया करेगा। गुरदासपुर में रणजीत सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए उसके आरोपियों को भी न बख्शने की बात कही गई है। पोस्ट के अंत में खालिस्तान समर्थक नारे भी लिखे गए हैं, जिनमें खालिस्तान के समर्थन और खालसा राज की बात दोहराई गई है।

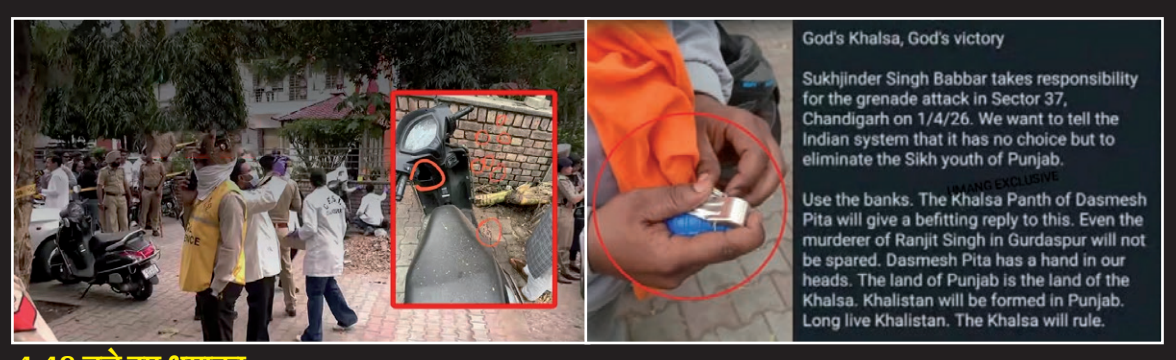

4.48 बजे हुए धमाका

चंडीगढ़ सेक्टर-37 में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर बुधवार शाम करीब 4:48 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में कार्यालय के बाहर खड़ी कार का शीशा टूट गया। काले रंग की एक एक्टिवा क्षतिग्रस्त हो गई और चहारदीवारी पर 50 से अधिक स्थानों पर छर्रों के निशान देखने को मिले। एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि विस्फोट के लिए क्रूड बम का इस्तेमाल किया गया जिसमें श्रैपनेल और फ्रैगमेंटेशन मटेरियल का प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले क्रूड बम का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में एक घटना में किया गया था।

एनआईए की टीम पहुंची - धमाके के तुरंत बाद कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी मच गई। भाजपा कार्यालय के साथ स्थित रोटरी एंड ब्लड बैंक सोसाइटी और लॉ भवन में मौजूद लोग भी बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही एसएसपी कंवरदीप कौर, आईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की टीमों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस हमले में सेकेंड ग्रेड विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जिसमें धातु के टुकड़ों यानी श्रैपनेल को शामिल किया गया था ताकि नुकसान ज्यादा हो सके। जांच में यह भी सामने आया है कि धमाका एक काले रंग की एक्टिवा (नंबर सीएच01डीबी6033) के पास हुआ, जो रोजी नामक महिला के नाम पर पंजीकृत है। सीसीटीवी फुटेज की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सड़क की ओर से कोई संदिग्ध वस्तु फेंकी गई जो एक्टिवा के पास गिरते ही विस्फोट में बदल गई। हालांकि, यह भी जांच की जा रही है कि कहीं विस्फोटक वाहन में पहले से प्लांट तो नहीं किया गया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस घटना के तार प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़ने की आशंका है। इसके अलावा इस हमले को पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी कुमार शर्मा से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

तुम सुंदर हो, तुम्हारी...अकोला पुलिस के एएसआई ने महिला से की बेटी की मांग, अब हुआ निलंबित

अकोला, एजेंसी | महाराष्ट्र के अकोला में एक सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) ने कथित तौर पर हिरासत में ली गई एक महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करते हुए पैसे के बदले अपनी बेटी को उसके पास भेजने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वह फिलहाल फरार है। आरोपी अधिकारी राजेश जाधव ने कथित तौर पर ड्यूटी पर रहते हुए महिला से पैसे के बदले अपनी बेटी को उसके घर भेजने की मांग की। महिला को 80 लाख रुपये के धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस स्टेशन में रहने के दौरान, जाधव ने कथित तौर पर उससे कहा, 'तुम बहुत सुंदर हो; तुम्हारी बेटी भी सुंदर होगी। उसे मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। इसके बाद महिला ने थाने में मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने जाधव को ड्यूटी से हटा दिया। अकोला के पुलिस अधीक्षक अर्चित चंदक ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जाधव फिलहाल फरार है और उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए तीन पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। जांच का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जुमले ने पुष्टि की कि औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है और तुरंत कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. आशा मिर्गे ने कहा कि जाधव के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आई थीं। लगभग एक दशक पहले, पारिवारिक विवादों और महिलाओं के प्रति कथित अनुचित व्यवहार से संबंधित रिपोर्टें आई थीं, जिनमें एक महिला पुलिस अधिकारी से जुड़ी घटना भी शामिल है।

नारायण साईं तलाक केस में पत्नी ने मांगे पांच करोड़ रुपये, कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी; फैसला सुरक्षित

इंदौर, एजेंसी | तीन साल से ज्यादा समय से चल रहे प्रवचनकार आसाराम के बेटे नारायण साईं के तलाक को लेकर लगाई गई याचिका में सुनवाई पूरी हो गई है। फैमिली कोर्ट जल्दी ही इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

नारायण साईं की पत्नी जानकी इंदौर में रहती हैं। उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए पांच करोड़ रुपये के स्थायी गुजारा भत्ता नारायण साईं से दिलवाने की मांग की है। बुधवार को कोर्ट में इस मामले पर अंतिम बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

इंदौर निवासी जानकी भी आश्रम की सेवादार थीं। नारायण साईं ने करीब पंद्रह साल पहले उनके साथ विवाह किया था, लेकिन वह अपने साथ नहीं रखता था। जानकी ने वर्ष 2023 में तलाक की याचिका इंदौर के कोर्ट में दायर की थी।

अमेरिका ही छोड़ सकता है नाटो, दगाबाजी से भड़के ट्रंप ने कहा- कागज के शेरों के साथ क्या रहना?

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो के टूटने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान संघर्ष में सहयोगी देशों के शामिल न होने और सैन्य बल का इस्तेमाल करके होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में मदद न करने के बाद अमेरिका नाटो से अलग होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे नाटो से कभी प्रभावित नहीं हुए और हमेशा से जानते थे कि यह सिर्फ कागजी शेर है। उन्होंने आगे कहा कि अब इस रक्षा संधि से अमेरिका को हटाना असंभव है। यह अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि व्हाइट हाउस अब यूरोप को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि सहयोगी देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए युद्धपोत तैनात करने

की ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे संघर्ष के बाद नाटो की अमेरिकी सदस्यता पर पुनर्विचार करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, 'हाँ, बिल्कुल। मैं कहूंगा कि अब पुनर्विचार संभव नहीं है। मैं नाटो से कभी संतुष्ट नहीं था। मैं हमेशा से जानता था कि वे सिर्फ कागजी शेर हैं, और पुतिन भी यह जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के देशों द्वारा होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने में मदद करने से इनकार करने पर ट्रंप बेहद नाराज़ हैं। होर्मुज एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिससे होकर मध्य पूर्व से दुनिया के लगभग 30 प्रतिशत तेल और ऊर्जा की आपूर्ति होती है। 28 फरवरी को शुरू हुए मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा अपने क्षेत्र पर किए गए बड़े पैमाने पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है।

इससे पहले, ट्रंप ने ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए और होर्मुज जलडमरूमध्य से अपना तेल खुद निकालना चाहिए। यह प्रतिक्रिया ईरान के खिलाफ संघर्ष में इन देशों की निष्क्रिय प्रतिक्रिया के जवाब में थी। उन्होंने लिखा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के कारण जेट ईंधन न मिलने वाले सभी देशों, जैसे कि ब्रिटेन, जिसने ईरान को कमजोर करने में शामिल होने से इनकार कर दिया।

शासकीय स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों का बढ़ा आकर्षण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने बच्चों को निःशुल्क साइकिल और पुस्तकें की वितरित

• भोपाल संवाददाता

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश के विकास के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक 'स्कूल चले हम' अभियान चलेगा और बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शासकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या शून्य करने पर स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे वर्ष 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में भी 32.4

प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गई है। यह शासकीय स्कूलों पर बढ़ते विश्वास का परिचायक है। राज्य सरकार ने मौजूदा सत्र में स्कूलों में 1 करोड़ 45 लाख नामांकन करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 369 भव्य सांदीपनि विद्यालयों की शुरुआत की गई है, जो देश में सबसे अच्छे स्कूल हैं। मध्यप्रदेश के सांदीपनि विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पीएमश्री स्कूल भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में महती भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

जन विश्वास विधेयक को बीजेपी ने बताया गेम चेंजर, विपक्ष ने उठाए सवाल

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | मामूली प्रक्रियात्मक और तकनीकी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाले 'जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026' को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि यह विधेयक संदेह से विश्वास की ओर ले जाने वाला और उद्यमियों को मुक्त माहौल प्रदान करने वाला है। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर बुधवार को तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई और भाजपा ने जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक

बताया, वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार सीमित होंगे और गैर-सरकारी संगठनों पर सरकार का नियंत्रण सख्त होगा। वहीं, लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि जो कोई भी भाजपा के साथ गया है, उसका बुरा हाल हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया सबसे बड़ा मुकदमेबाज, ठोका 25,000 जुर्माना

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच के एक फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। मामला एक सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल की बर्खास्तगी से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी बर्खास्तगी खत्म करते हुए, उसका 25% वेतन भी वापस करने का फैसला सुनाया था। केंद्र पर जुर्माना लगाते हुए केस खारिज - सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र के स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) खारिज कर दिया है। लाइवलॉ डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां

की बेंच ने एसएलपी डालने के केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए कहा-

हम समझ नहीं पाए कि भारत सरकार और अन्य लोग हाई कोर्ट के डिविजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए इस अदालत तक क्यों आए। हम 25,000 जुर्माने के साथ एसएलपी को खारिज करते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार को सबसे बड़ा मुकदमेंबाज बताया और कहा कि इसी वजह से अदालत में इतने केस लंबित हैं। उन्होंने कहा, 'यह केस जुर्माने के साथ खारिज होना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने सजा को गलत ठहरा कर आदेश रद्द करके राहत दे दी, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए।

ईरान के लिए चंदा एकत्रित करते करते कश्मीरी महिला ने भारतीय सेना का किया अपमान, जवानों को शराबी बताया

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कश्मीरी महिला ईरान की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करती नजर आ रही है। लेकिन जब उससे यह सवाल पूछा गया कि क्या इसी तरह का अभियान भारतीय सेना के लिए भी चलाया जा सकता है, तो उसने भारतीय जवानों को शराबी बताकर न केवल सेना का अपमान किया बल्कि देशभक्ति की भावना पर भी चोट पहुंचाई। भारतीय जवानों को शराबी बता रही इस महिला या ऐसी सोच रखने वाले लोगों को समझना होगा कि भारतीय सेना केवल सीमा पर खड़ी रहने वाली ताकत नहीं है, बल्कि वह देश के हर नागरिक की जीवन रेखा है, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील और कठिन भौगोलिक क्षेत्र में।

देखा जाये तो कश्मीर भले

अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र आतंकवाद के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं का भी लगातार सामना करता है। भारी बर्फबारी, भूकंप, बाढ़ और कठोर सर्दी यहां की सच्चाई है। ऐसे समय में जब आम जीवन पूरी तरह ठहर जाता है, तब एक ही संस्था है जो बिना थके बिना रुके लोगों के साथ खड़ी रहती है और वह है भारतीय सेना। यह सेना नशे में नहीं बल्कि देश सेवा के जुनून में डूबी रहती है तभी कठिन से कठिन मौसमी परिस्थितियां या दुश्मन की ओर से पैदा की जाने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी जवानों के हौसले को हिला नहीं पातीं।।

इस महिला को पता होना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में जब कश्मीर के दूर दराज इलाके बर्फ की मोटी परतों में दब जाते हैं, तब गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे में बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों के लिए हर पल जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। लेकिन इन्हीं हालात में भारतीय सेना के जवान कई कई किलोमीटर तक बर्फ को चीरते हुए पैदल चलते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। कई बार वे बीमार लोगों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। क्या यह काम कोई शराबी कर सकता है या यह केवल वही कर सकता है जो देश सेवा के जज्बे से भरा हो?

असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी का यादगार अनुभव, महिला श्रमिकों संग चायपत्ती तोड़ी, सेल्फी भी ली

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान का दौरा किया, जहां उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की और राज्य के विश्व प्रसिद्ध चाय उद्योग में उनके योगदान की सराहना की। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि चाय असम की आत्मा है। यहां की चाय दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। आज सुबह डिब्रूगढ़ में, मैं एक चाय बागान गया और वहां काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। यह एक बहुत ही यादगार अनुभव था।

चाय बागान की झलकियाँ साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हर चाय बागान परिवार के प्रयासों

पर बहुत गर्व है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने असम के गौरव को बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद महिलाओं ने अपनी संस्कृति के बारे में बात की और निश्चित रूप से एक सेल्फी भी ली! चाय बागान श्रमिकों के साथ पीएम मोदी की बातचीत चाय से उनके व्यक्तिगत जुड़ाव को भी दर्शाती है, जिसे वे अक्सर अपने भाषणों में उजागर करते हैं। वे अपने बचपन को याद करते हैं जब वे गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद करते थे।

असम विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट जैसे जिले इस उद्योग की रीढ़ हैं। यह क्षेत्र लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है और भारत के चाय निर्यात और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले असम भर में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं, एक चुनैवी सभा में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि यह चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को आकार देगा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने का है... भाजपा असम में फिर से सरकार बनाएगी और हैट्रिक बनाएगी। उनकी ये टिप्पणियां आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य भर में पार्टी के प्रचार अभियान तेज करने के बीच आईं, जो 9 अप्रैल को होने वाले हैं। मोदी ने कहा कि असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है।

मोदी ने कहा कि ये जो सामने जनसमुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों-बेटियों का ये आशीर्वाद, ये प्यार इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इस मैदान में भी हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है, मैं यहां तीसरी बार आया हूं।

बसुरिया मे समीक्षा बैठक आयोजित

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

राजेश नीरस. गत दिवस ग्राम बसुरिया के शास. हायर सेकंडरी स्कूल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे प्राचार्य लखन लाल मेहरा द्वारा विगत सत्र 2025-26 की उपलब्धियों के लिये जिसमें परीक्षा परिणाम एवं अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया एवं नवीन सत्र 2026-27 के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई। रूपरेखा अनुसार विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों के प्रवेश को लेकर मंथन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि शिक्षकों का समूह तैयार कर पालकों से समन्वय स्थापित किया जाये और बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाये जिससे शाला में सत्र 2026-27 में अधिक से अधिक नये बच्चों का प्रवेश हो सके। इस बैठक मे समस्त शिक्षक उपस्थित रहे

डूंगरिया मे स्कूल चलें हम अभियान प्रारंभ

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

राजेश नीरस. बुधवार को क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया के शासकीय हाईस्कूल मे स्कूल चलें हम अभियान का भव्य शुभारम्भ हुआ। अभियान के पहले दिन प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया जिसमें मां सरस्वती पूजन के उपरांत अतिथियों का स्वागत फूलमालाओं के साथ किया गया। इसके पश्चात नव प्रवेशी विद्यार्थियों का भी फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम सरपंच अशोक गुर्जर,जनपद सदस्य बुद्धा ठाकुर जी , दादुवीर दुबे एवं ग्राम के अन्य वरिष्ठ जन तथा भूतपूर्व छात्रों की भी उपस्थित रही। साथ ही विद्यालय परिवार के प्राचार्य देवेंद्र पगारे एवं समस्त स्टाफ की उपस्थिति रही। इस मौक़े पर विद्यार्थियों को प्रवेश उत्सव का लाइव कार्यक्रम स्मार्ट बोर्ड पर दिखाया गया एवं अंत मे चॉकलेट तथा प्रसाद वितरण किया गया इसके पश्चात विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया गया।

सांदीपनि सीएम राइज विद्यालय मनगवां में 'स्कूल चलें अभियान' का शुभारंभ

विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बच्चों को तिलक चंदन किया एवं पुस्तकों का वितरण किया गया

साधना एक्सप्रेस मनगवां, रीवा।

सांदीपनि सीएम राइज विद्यालय मनगवां में 'स्कूल चलें अभियान' का भव्य शुभारंभ उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनगवां विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर अभियान की शुरुआत की।

कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत के साथ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला और बच्चों में विशेष उमंग नजर आई। अपने उद्बोधन में विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी अपने माता-पिता और समाज की सच्ची उम्मीद होते हैं। उन्होंने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासन बनाए रखने और अपनी कक्षा ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा को जीवन की सफलता का मूल आधार बताया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता जगजीवन लाल तिवारी, जिला सलाहकार समिति सदस्य लवकुश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि प्रियंका तिवारी, विष्णुदेव कुशवाहा, नगर पंचायत अध्यक्ष बूटला बंसल, पार्षद महेंद्र पटेल, मुकेश तिवारी, पूनम बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से मुलाकात और चर्चा की

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के संसद सदस्यों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास संबंधी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय संचार और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन , केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के साथ श्री महेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसके पहले मध्यप्रदेश के सांसदों से विकास के विभिन्न मुद्दों पर वन-टू-वन चर्चा की। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों के साथ मध्यप्रदेश भवन में हुई बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

निगम-मंडलों में नियुक्तियों की सूची तैयार

केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिलते ही होगी जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का लंबा इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में संभावित नामों की सूची लगभग तय कर ली गई है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल रहे। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार इस सूची में 50 से ज्यादा नेताओं के नाम शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सूची वापस भेजकर कुछ और नाम जोड़? को कहा था, जिसके बाद प्रदेश संगठन ने इसमें संशोधन किया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस सूची को लेकर दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय

नेतृत्व की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियों का ऐलान किया जाएगा। संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में इन पदों पर नियुक्तियां हो सकती हैं। जहां-जहां नामों को लेकर विवाद की स्थिति है, वहां फिलहाल नियुक्तियां टाली जा सकती हैं। बाकी पदों पर सहमति बनने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बता दें इससे पहले प्रदेश में 123 नगर परिषद और 46 नगर पालिका में 750 से अधिक एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई। साथ ही ग्वालियर से आने वाले फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता जयभान सिंह पवैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। 4 और 5 को होगी संघ की समन्वय बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 4 और 5 अप्रैल को भोपाल के शारदा विहार में होगी। इसमें संघ के 37 अनुशांगिक संगठनों के साथ भाजपा भी शामिल होगी। समन्वय बैठक में पार्टी के ओर से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। समन्वय बैठक की तैयारियों को लेकर सीएम हाउस में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की। इस बैठक में संघ पदाधिकारी दीपक विस्पुते, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। भोपाल में होने वाली समन्वय बैठक में संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल होंगे। अरुण कुमार संघ और भाजपा में समन्वय का काम देखते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक हाल ही में हुई है। ऐसे में राजधानी में होने वाली समन्वय बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में संघ एक साल की कार्ययोजना पर भी चर्चा करेगा। इसके अलावा संघ अपने 32 अनुशांगिक संगठनों के दायित्वों में बदलाव को लेकर भी चर्चा करेगा। संघ की इस बैठक से पहले सत्ता और संगठन के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। आरएसएस ने अपनी संगठनात्मक संरचना में बदलाव किया है।

सत्ता-संगठन में नियुक्तियों पर जोर

दरअसल प्रदेश में साल 2027 में नगरीय निकाय चुनाव होना है। इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इधर, सरकार और संगठन पिछले कई महीने से राजनीतिक नियुक्तियां करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन अब तक निगम मंडल और बड़े शहरों के विकास प्राधिकरणों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। संघ इनमें जल्द नियुक्ति का पक्षधर है। संघ की इच्छा को ध्यान में रख नगर पालिका और नगर परिषदों में 768 एल्डरमैन की नियुक्तियां की गई हैं। अब जल्द ही प्रदेश के 16 नगर निगमों में भी एल्डरमैन की नियुक्ति करने की तैयारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को कार्यभार संभाले हुए करीब 8 महीने हो गए हैं। अब तक संगठन की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। समन्वय बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित करेगी। भाजपा की पिछली कार्यकारिणी में 237 सदस्य थे। इस बार कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संकेत दे दिए हैं कि अप्रैल में विस्तारित टीम के साथ पहली कार्यसमिति बैठक आयोजित होगी। इससे पहले सभी नियुक्तियां की जा रही है। इस बार कार्यकार्यकारिणी में युवा और नए चेहरों को शामिल करके पार्टी संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश में है। इसके लिए प्रदेश स्तर ही नहीं, अब जिला और मंडल स्तर पर भी संगठनात्मक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं।

मप्र में प्रोफेसर्स की वरिष्ठता सूची गड़बड़ाई

दो हिस्सों में बंटे विभागीय कार्यालयों ने बढ़ाई उलझन

भर्ती नियमों में हर दस साल में यूजीसी रेगुलेशन को समन्वित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश में लंबे समय से इसमें संशोधन नहीं किया गया।

भोपाल। मप्र में उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली इस कदर गड़बड़ाई हुई है कि एक को सुधारने में दूसरी उलझन बढ़ जा रही है। खासकर प्रोफेसरों की वरिष्ठता सूची तो ऐसी गड़बड़ाई है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आलम यह है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 2011 के बाद से असिस्टेंट प्रोफेसरों की वरिष्ठता सूची ही नहीं बनाई है, जबकि नियमानुसार यह ग्रेडेशन लिस्ट हर साल या अधिकतम 3 साल में जारी होनी चाहिए थी। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2024 में तत्कालीन आयुक्त निशांत वरवड़े के कार्यकाल में जो प्रोविजनल सूची जारी हुई थी, विभाग ने अब उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब विभाग 2026 में वापस पीछे लौट गया और 2012 की प्रोविजनल सूची जारी कर दी है। एक ओर इससे प्रोफेसर्स की सीनियरिटी को लेकर असमंजस और बढ़ गया हैं। नियमानुसार 2024 में जारी सूची को अद्यतन मानते हुए 2023 तक की स्थिति स्पष्ट मानी जा रही थी। इसके विपरीत 2026 में 2012 की प्रोविजनल सूची जारी होना यह दशार्ता है कि अभी विभाग को केवल 2011 तक की स्थिती स्पष्ट है। 2012 से नियमित तौर पर सूची न बनाना और अब पिछले दो साल में आयुक्त कार्यालय और मंत्रालय स्तर पर अलग-अलग कार्यवाही करना प्रश्न खडे करता है। सूत्रों के अनुसार नई सूची पर विभाग को ढेरों आपत्तियां मिल चुकी हैं। इन विसंगतियों के चलते आने वाले दिनों में कोर्ट केस बढने.की पूरी संभावना जताई जा है, जिससे पूरी प्रक्रिया और अधिक उलझ सकती है। सामने आ रही खामियां इधर, 2012 की सूची में 2006 से 2009 के बीच के कई ऐसे शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर बताया गया है, जो अब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन चुके हैं। इन्हें वर्ष 2018 में डीपीसी की अनुशंसा के बाद प्रोफेसर का पदनाम दिया जा चुका था। पदनाम का लाभ लेकर 933 शिक्षक प्रोफेसर बन चुके हैं और आगे चलकर इनमें से कई एडिशनल डायरेक्टर, कुलगुरु व प्राचार्य जैसे पदों तक पहुंच गए। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने अपने से वरिष्ठ प्रोफेसरों की गोपनीय प्रविष्टियां (सीआर) तक लिखीं। वहीं करीब 70 प्राफेसर जिन्हें यह लाभ नहीं मिला, उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब 2025 में कोर्ट में विभाग ने कहा है कि भर्ती नियमों में पदनाम का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में पदनाम के आधार पर हुए प्रमोशन, नियुक्तियां और उनसे जुड़े प्रशासनिक निर्णयों की स्थिति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भर्ती नियमों में हर दस साल में यूजीसी रेगुलेशन को समन्वित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश में लंबे समय से इसमें संशोधन नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार 1990 के बाद 2015 में केवल आंशिक संशोधन किया गया। अब कहीं 2018 के नियमों से प्रोफेसरों की सीआर लिखी जा रही है, जबकि कई प्रक्रियाएं पुराने नियमों से संचालित हो रही हैं। यही असंगति विभागीय निर्णयों को और उलझा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार हर साल ग्रेडेशन यानी सीनियरिटी लिस्ट बननी चाहिए, लेकिन 2011 के बाद से सूची नहीं बनी। 2024 में तत्कालीन आयुक्त ने जो सूची बनाई थी, अब वह अस्तित्व में नहीं है।

मध्य प्रदेश में बार-बार क्यों बदल रही गेहूं खरीदी तारीख, अब 10 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया

तीसरी बार तारीख बदलने से उठे सवाल, कांग्रेस का आरोप-किसानों को कर्ज लेने पर मजबूर कर रही सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश के कई संभागों में खरीदी 1 अप्रैल के बजाय 10 अप्रैल से शुरू होगी। गेंहूं खरीदी की बार-बार बढ़ती तारीख ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि सरकार ऐसा करके किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर कर रही है। अब एक बार फिर बदले हुए सरकारी फैसले के अनुसार, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा, जबकि अन्य संभागों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। यह निर्णय गेहूं खरीदी के लिए गठित कैबिनेट मंत्रियों की समिति द्वारा लिया गया है। गौरतलब है कि यह तीसरी बार है जब

खरीदी की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 1 फरवरी से खरीदी शुरू होनी थी, जिसे बाद में 16 मार्च किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल की तारीख तय हुई, लेकिन अब इसे फिर बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है। लगातार हो रहे बदलाव के पीछे वारदाने (बोरी) की कमी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। किसान कर्ज लेने को मजबूरः मुकेश नायक इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि बार-बार तारीख बढ़ने से किसान आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे हैं और किसानों के घरों में भी शादियां हैं, लेकिन गेहूं की बिक्री न होने के कारण उन्हें खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि खुले बाजार में गेहूं का दाम समर्थन मूल्य से करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल कम मिल रहा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने की जल्द खरीदी शुरू करने की मांग कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गेहूं खरीदी शुरू की जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। वहीं, सरकार का कहना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर तय नई तारीख से खरीदी सुचारु रूप से शुरू की जाएगी। जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि बदलती तारीखों के कारण किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे उनमें आक्रोष भी पनप रहा है।

अब आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में मिलेगा वेतन

भोपाल। मध्यप्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जरूरी और अच्छी खबर सामने आई है। आउटसोर्स कर्मचारी को अब सीधे खाते में वेतन मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। कर्मचारियों को बिचौलियों और कंपनियों के शोषण से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में एंट्री फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर वसूली करने वाली कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 1 अप्रैल से सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नई गाइडलाइन लागू होगी। आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी।

आपके व्यवहार और बयानों से पार्टी की छवि खराब न हो

समन्वय बैठक में संघ ने मंत्रियों को दी सख्त हिदायत

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा के मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि उनके आचरण, व्यवहार और बयानों से पार्टी की छवि खराब न हो। संघ ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि कार्यकर्ता बिजली की तरह चमकने (क्षणिक चमक) के बजाय दीपक की तरह जलकर (निरंतर सेवा) समाज की सेवा करें। दरअसल, राजधानी के सुशासन भवन में सोमवार को संघ की मौजूदगी में सरकार और संगठन की समन्वय बैठक हुई। सूत्रों की मानें तो बैठक में पिछले कुछ महीनों से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की नाराजगी को लेकर चर्चा हुई है और उन्हें सरकार के साथ काम करने की समझाइश दी गई है। इसके अलावा

बैठक में सरकारी पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों पर भी मंथन किया गया है। जानकारी के अनुसार, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन स्कूल में अचानक बुलाई गई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा की समन्वय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी, दीपक विस्तपुते, स्वप्निल कुलकर्णी के अलावा प्रांत प्रचारक स्तर के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है, जिससे इस बैठक की अहमियत बढ़ गई है। तकरीबन पांच घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। सूत्रों की मानें तो बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की नाराजगी पर भी चर्चा की गई है। बताया गया है कि दोनों नेताओं से कहा गया है कि उनके किसी भी तरह के कार्यों से सरकार और पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बताया गया है कि दोनों मंत्रियों ने संघ पदाधिकारियों के सामने अपनी बातें रखी है। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भी चचर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि अचानक बुलाई गई बैठक दिल्ली के निर्देश पर की गई है। पिछले कुछ दिनों से मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बातें रखी गई है, तो उनके द्वारा कैबिनेट की बैठक में अनुपस्थिति व अन्य कार्यक्रमों से दूरी बनाने की खबर भी दिल्ली पहुंची है। ऐसे में संघ और भाजपा संगठन ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए संघ और संगठन की समन्वय बैठक भोपाल में बुलाने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें कहा गया था कि यह मामला जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। राज्यसभा उम्मीदवार-मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मंथन होने की खबर है। जानकारों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व चाहती है कि मध्यप्रदेश की खाली हो रही राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा जाए। ये तीनों उम्मीदवार मध्यप्रदेश से ही हो। बैठक में कांग्रेस के खाते वाली सीट भाजपा को कैसे मिले, इस पर भी चर्चा की गई है। तीसरी सीट पर पार्टी किसी ऐसे नेता को उम्मीदवार बना सकती है, जो शीर्ष नेतृत्व के करीबी है। सूत्रों की मानें तो बैठक में प्रदेश मंत्रिमण्डल के विस्तार और फेरबदल को लेकर भी मंथन किया गया है। दरअसल केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा संभावित फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पहले ही हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मंत्रिमण्डल विस्तार और फेरबदल को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जब भी फेरबदल होगा, तो प्रदेश सरकार के कुछ बड़े नेता दिल्ली जा सकते है। इनमें कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के नाम की भी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

रतलाम में अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर करारा प्रहार

राज्यपाल ने की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष विभाग की समीक्षा

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि दीन-दुखियों की सेवा मानवता की सेवा है। इससे आत्म संतोष मिलता है। प्रदेश को सिकल सेल और टी.बी. मुक्त बनाने के प्रयासों में सेवा भाव को सर्वोपरि होना चाहिए। राज्यपाल पटेल मंगलवार को लोकभवन में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा जवाहर खण्ड सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि सिकल सेल रोगियों को आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और पात्रता आदि की समुचित जानकारी दें। प्रदेश स्तरीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शून्य से 40 वर्ष तक के व्यक्तियों की विशेष तौर पर जाँच करें। जाँच शिविरों में आमजन को बताएँ कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया का इलाज कवर होता है। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत सिकल सेल रोगियों के इलाज की जिलेवार समीक्षा की। **जन प्रतिनिधि पोषण आहार वितरण में करें सक्रिय सहयोग** - राज्यपाल पटेल ने बैठक में टी.बी. उन्मूलन

कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को टी.बी. मुक्त बनाने स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विशेष कर जनजातीय क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि टी.बी. रोगियों को पोषण आहार वितरण में सक्रिय सहयोग करें। राज्यपाल पटेल ने निःक्षय मित्रों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक निःक्षय मित्रों को जोड़कर पोषण आहार वितरण को बढ़ाने के प्रयासों पर बल देने के निर्देश दिए है। **खनन क्षेत्रों में भी कराएं टी.बी. की सघन जाँच**- राज्यपाल पटेल ने खनन क्षेत्रों में निवासरत और कार्यरत व्यक्तियों की टी.बी. जाँच कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सिकल सेल जाँच लक्ष्य एवं पूर्ति, जेनेटिक कार्ड वितरण, हाईड्राक्सी यूरिया की उपलब्धता, गर्भावस्था में माताओं और शिशुओं का सिकल सेल प्रबंधन, सिकल सेल रोगियों को आयुष्मान कार्ड वितरण, आयुष्मान योजना का लाभ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरण, 125 दिवसीय सिकल सेल जागरूकता अभियान आदि विस्तार से समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आयुष्मान कार्ड की प्रगति, सिकल सेल और टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न मानको को शत-प्रतिशत पूरा करने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। राज्यपाल पटेल को आयुष विभाग के प्रमुख सचिव शोभित जैन ने जिलेवार दवा वितरण, घर-घर दवाई वितरण, जाँच आदि कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। श्री जैन ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में औषधि वितरण के विशेष प्रयासों और नवाचारों की जानकारी भी दी। राज्यपाल पटेल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की उपलब्धियों, सघन स्क्रीनिंग, 100 दिवसीय निःक्षय अभियान, निःक्षय मित्र, पोषण आहार वितरण आदि की जानकारी दी। राज्यपाल पटेल के निदेर्शानुसार प्रारंभ किए गए अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में विद्यार्थियों की टी.बी. जाँच, परामर्श, उपचार आदि के बारे में भी बताया। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अशोक कुमार बर्णवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और लोकभवन के अधिकारी मौजूद रहे।

आज से घर-जमीन खरीदना होगा महंगा, रजिस्ट्री के लिए जेब करनी होगी ढीली

नगर निगम क्षेत्र में निर्माण दरों में 1000 रुपये की वृद्धि की गई

भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा। रजिस्ट्री की दरें बढने वाली हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने राज्य के 55 जिलों में 5 लाख 5 हजार स्थानों में से 65 हजार स्थानों पर प्रॉपर्टी की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही निर्माण की दरों को भी बढ़ाई गई है। इससे लोगों का घर का सपना उनके बजट से बाहर होता जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रॉपर्टी की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिए गए थे। इसके बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इसे हरी झंडी दे दी थी। राज्य के 65 हजार स्थानों पर औसत वृद्धि 16 फीसदी तक की गई है। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। यही वजह है कि रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा। वहीं, निर्माण दरों में 7 से 14 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। निर्माण दरों में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। ये नगर निगम क्षेत्र में 13 हजार से बढकर 14 हजार रुपये हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 6000 से बढकर 7000 रुपये हो गई है। इस वजह से मकान की लागत तो बढ़ेगी ही इसके साथ ही रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी भी ज्यादा देनी होगी। भोपाल में कितनी बढ़ेंगी दरें मध्य प्रदेश में हर

साल औसतन प्रॉपर्टी की दरों में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है। पिछले साल ये 13 प्रतिशत थी जो अब 16 फीसदी हो गई है, जो कि 3 फीसदी है। राजधानी भोपाल में 12 परसेंट की औसत वृद्धि की गई है। वहीं कई स्थानों पर 740 स्थानों पर 1 से लेकर 181 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे यहां प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है।

बिजली बिल में बढ़ोतरी

नए नियमों के तहत बिजली की दरों में औसतन पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी स्लैब के अनुसार अलग-अलग होगी। जानकारी के अनुसार 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को करीब 80 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वालों का बिल 150 रुपये तक बढ़ सकता है। इससे गर्मी के मौसम में पहले से ही बढ़ी बिजली खपत के बीच उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कचरा प्रबंधन के नए नियम शहरों में अब कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य किया जा रहा है। गीला, सूखा और अन्य प्रकार के कचरे को अलग नहीं करने पर जुमार्ना लगाया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं, जिनके तहत घरों, होटलों और संस्थानों को कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा। इससे साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

रेलवे रिजर्वेशन नियमों में बदलाव

रेलवे रिजर्वेशन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब वेटिंग टिकट और कंफर्मेशन से जुड़े नियमों को और पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही टिकट कैंसिलेशन और रिफंड प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नए नियमों के लागू होने से यात्रा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

आयकर प्रणाली में सुधार

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें टैक्स भुगतान और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान किया गया है। डिजिटल माध्यमों के जरिए भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और समय की बचत होगी।

|| संपादकीय ||

डिजिटलीकरण की रफ्तार और 'डिजिटल जहर' का खतरा

आज हमारा देश भारत तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर है, और कहना ग़लत नहीं होगा कि इसमें स्मार्टफोन विशेषकर एंड्रॉयड का सबसे बड़ा योगदान है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर जहां एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 3.9 अरब (390 करोड़) है, वहीं भारत में वर्ष 2025–2026 के अनुमान के अनुसार कुल स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 75 करोड़ (750 मिलियन) तक पहुंच चुकी है। इनमें से लगभग 89%-90% स्मार्टफोन एंड्रॉयड आधारित हैं। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो भारत में करीब 65-70 करोड़ लोग एंड्रॉयड फोन का उपयोग कर रहे हैं।यह भी कहा जा सकता है कि आज हर 10 में से लगभग 9 लोग एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे देश में सस्ते डेटा प्लान, किफायती स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं का विस्तार इस तेजी के प्रमुख कारण हैं।

हालांकि, इस डिजिटल क्रांति का एक चिंताजनक पहलू भी सामने आ रहा है-'डिजिटल जहर' अर्थात मोबाइल और स्क्रीन की बढ़ती लत, जो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। आंकड़े इस समस्या की भयावहता को स्पष्ट करते हैं। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि हमारे देश में 0-5 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन औसतन 2.2 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से लगभग दोगुना है। वहीं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन देखते हैं, जबकि उनके लिए स्क्रीन टाइम शून्य होना चाहिए।

इतना ही नहीं, यदि हम यहां पर स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें, तो एक अध्ययन के अनुसार 62.5% बच्चों में मध्यम से उच्च स्तर की स्क्रीन लत पाई गई है, और उनका औसत स्क्रीन टाइम लगभग 4 घंटे प्रतिदिन है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि भारत के 74% छात्र रोजाना 2 घंटे से अधिक स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जिनमें से 21% बच्चे 4 घंटे से भी अधिक समय मोबाइल, गेमिंग या सोशल मीडिया पर बिताते हैं। लगभग 70% माता-पिता का मानना है कि उनके बच्चे वीडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आदी हो चुके हैं। और भी चिंता की बात यह है कि 64% बच्चे सोशल मीडिया और गेमिंग के आदी हैं, जबकि केवल 20% बच्चों में किसी प्रकार की डिजिटल लत नहीं पाई गई है।एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज के समय में भारत में लगभग 90% किशोरों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है और 76% बच्चे मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भी डिजिटल लत को बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बताया है, क्योंकि यह उनकी पढ़ाई, एकाग्रता और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

इस डिजिटल लत के दुष्परिणाम भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। मसलन, ध्यान में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, पढ़ाई में गिरावट, सामाजिक दूरी, अकेलापन, मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि हाल ही में राज्यसभा में भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया, जहां यह बताया गया कि कई बच्चे प्रतिदिन 7-8 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं। इससे उनकी शिक्षा, सामाजिक जीवन और नींद पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।विशेषज्ञों ने इस स्थिति को 'डिजिटल गुलामी' तक करार दिया है, क्योंकि बच्चे मोबाइल के बिना स्वयं को असहज महसूस करते हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की होड़ बच्चों में हीन भावना, तनाव और अवसाद को बढ़ा रही है, वहीं ऑनलाइन बुलिंग जैसी समस्याएं भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। हाल ही में एक अमेरिकी अदालत ने भी यह माना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि उपयोगकर्ता बार-बार उन्हें इस्तेमाल करें, जिससे लत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने, स्कूलों में 'डिजिटल हेल्थ' को पाठ्यक्रम में शामिल करने और सोशल मीडिया तथा गेमिंग कंपनियों पर सख्त नियम लागू करने की मांग की गई है। साथ ही, अभिभावकों को यह सलाह दी गई है कि वे बच्चों पर केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय उनसे खुलकर संवाद करें, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें खेल-कूद तथा रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें।

अंततः, यह स्पष्ट है कि डिजिटल लत अब केवल एक आदत नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने जहां अभिव्यक्ति और सूचना के नए द्वार खोले हैं, वहीं उनका अत्यधिक उपयोग बच्चों और किशोरों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहा है। यदि समय रहते प्रभावी और संतुलित कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर गहरा और दीर्घकालिक होगा। इसलिए सरकार, शैक्षणिक संस्थान, अभिभावक और समाज-सभी को मिलकर जागरूकता, संतुलित उपयोग और सकारात्मक संवाद के माध्यम से इस 'डिजिटल जहर' से बच्चों और युवाओं को बचाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने और कूटनीति को विफल बताने वालों को यह रिपोर्ट देखनी चाहिए

> देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने वाले और मोदी की विदेश नीति को विफल बताने वाले विपक्षी नेताओं को यह देखना चाहिए कि जब भारत के सामने ऊर्जा संकट मंडराया तो दुनिया के वही देश मदद के लिए खड़े हो गए जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों तक भरोसे का रिश्ता बनाया था। खासकर अफ्रीकी देशों से बढ़ते आयात ने यह साबित कर दिया है कि भारत ने समय रहते अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया था। आज वही रिश्ते और रणनीतिक फैसले भारत की ढाल बनकर खड़े हैं और यही असली कूटनीति की ताकत है।

देखा जाये तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को झकझोर दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से भारत पहले अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है उस पर दबाव बढ़ने से कई तरह की अटकलें लगाई गईं। लेकिन भारत न तो घबराया और न ही संकट में फंसा। इसका कारण है मोदी सरकार की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और समय रहते उठाए गए रणनीतिक कदम।

आज स्थिति यह है कि भारत में कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की उपलब्धता एक महीने पहले की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुचारु बनी हुई है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित रणनीति का परिणाम है।

देखा जाये तो सबसे बड़ा बदलाव आया है ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में। एक दशक पहले तक भारत केवल 27 देशों से कच्चा तेल लेता था, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। अमेरिका, रूस, कनाडा, नार्वे से लेकर अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया और अंगोला तक भारत ने अपने ऊर्जा संबंधों का विस्तार किया है। एलएनजी के लिए कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी और मोजाम्बिक जैसे नए साझेदार जुड़े हैं।

यही नहीं, रणनीतिक भंडारण की दिशा में भी भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पिछले 11 वर्षों में 5.3 मिलियन टन का रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया गया है और अतिरिक्त क्षमता पर तेजी से काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत के पास आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है।

मोदी सरकार ने केवल आपूर्ति बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि प्रबंधन को भी मजबूत किया। चौबीसों घंटे निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया और एक अंतर मंत्रालयी समूह रोज बैठक कर हालात का आकलन कर रहा है। जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए और राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।

यहां सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीतिक सक्रियता। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और अमेरिका जैसे देशों के नेताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई और आपूर्ति बाधित नहीं हुई। यह वही देश हैं जिनसे भारत ने संकट के समय पहले भी सहयोग किया था और आज वही रिश्ते काम आए।

सामरिक दृष्टि से देखें तो यह पूरी स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति की बड़ी परीक्षा थी। पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ सकता था, लेकिन भारत ने अपनी निर्भरता घटाकर इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया। अब होर्मुज मार्ग पर निर्भरता घटकर लगभग तीस प्रतिशत रह गई है।

इसके रणनीतिक निहितार्थ और भी गहरे हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा कूटनीति का सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती मौजूदगी भारत को दीर्घकालिक सुरक्षा देती है। साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे विकल्पों को बढ़ावा देकर एलपीजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम हो रहा है।

आम जनता पर इसका सकारात्मक असर साफ दिख रहा है। रसोई गैस की आपूर्ति जारी है, भले ही घबराहट में बुकिंग बढ़ने से डिलीवरी में चार से पांच दिन का समय लग रहा हो, लेकिन कहीं भी गैस खत्म होने की खबर नहीं है। किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और पेट्रोल, डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है।

यह पूरा घटनाक्रम एक बात साफ करता है कि मोदी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को केवल नीतिगत मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा माना है। आज जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं तब भारत मजबूती से खड़ा है।

बहरहाल, विपक्ष को यह समझना होगा कि विदेश यात्राएं केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होतीं, बल्कि संकट के समय काम आने वाले रिश्ते बनाने के लिए होती हैं। और जब संकट आया, तो वही रिश्ते भारत के लिए कवच बन गए। यही है नई भारत की आक्रामक, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी कूटनीति।

• नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

मध्यस्थ नहीं, डाकिया

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक टीवी चर्चा के दौरान दावा किया था कि अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो पाकिस्तान जा रहे हैं। राजपूत लखनऊ में रहते हैं, लिहाजा पार्टी के क्षेत्रीय प्रवक्ता ही होंगे! उन्हें अमरीकी उपराष्ट्रपति के प्रवास की क्या जानकारी! लेकिन राजनीतिक दुष्प्रचार ऐसे ही किया जाता है। पाकिस्तान में अमरीकी प्रतिनिधियों को ईरान के समकक्षों या नुमाइंदों से बातचीत करनी थी। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में बताया गया था। उस टीवी चर्चा के दौरान लगभग सभी ने भारत की भूमिका पर सवाल उठाए। भारत को अलग-थलग कर दिया गया है, यह विश्लेषण भी सामने आया। पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका और अचानक बढ़ी हैसियत की तुलना में इसे भारत की गंभीर 'कूटनीतिक नाकामी' करार दिया गया। रविवार को यह संपादकीय लिखने तक न तो अमरीका और न ही ईरान ने ऐसी बातचीत की पुष्टि की थी। उपराष्ट्रपति वेंस अब भी अमरीका में ही हैं और ईरान अमरीका के साथ संवाद के लिए फिलहाल मानसिक और रणनीतिक तौर पर तैयार ही नहीं है। फिर मध्यस्थता का औचित्य क्या है? दरअसल कांग्रेस, वामदलों, सपा द्वारा समर्थित टीवी मीडिया पर यह सनसनीखेज चर्चा प्रायोजित लगती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर को फोन किया, लिहाजा पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर तय कर लिया गया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी दौर में प्रधानमंत्री मोदी से भी फोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी बात की थी। खाड़ी देशों के लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों, किंग, शेख, सुल्तान, अमीर आदि से भी बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को खारिज किया था और ऊर्जा ठिकानों पर विनाशक हमलों को स्वीकार्य नहीं माना था। भारत को मध्यस्थ इसलिए नहीं तय किया गया, क्योंकि भारत ऐसी मध्यस्थता के सैद्धांतिक, नीतिगत विरोध में रहा है। पाकिस्तान को 'अल्लाह' की मेहरबानी माननी चाहिए कि ईरान ने उस पर मिसाइल, ड्रोन हमले कर उसे मिट्टी-मलबा नहीं किया। ईरान ने अमरीका के प्रत्येक सहयोगी अथवा सैन्य बेस वाले देश पर लगातार हमले कर तबाही मचाई है। पाकिस्तान में मिस्र, तुर्किए, सऊदी अरब के विदेश मंत्री बैठक कर विमर्श कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान न तो कभी मध्यस्थ था और न ही यह कूटनीतिक दायित्व उसे दिया जा सकता है। अलबत्ता वह 'डाकिया' अथवा 'संदेशवाहक' जरूर बन सकता है और मेहनताने के तौर पर उसे कुछ डॉलर दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान इसलिए भी अमरीका-ईरान युद्ध में मध्यस्थ नहीं बन सकता, क्योंकि खुद उसकी अफगानिस्तान, टीटीपी, बलूच लड़ाकों के खिलाफ कई स्तर की जंग छिड़ी है। पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं और विरोधियों की भी हत्याएं की गई हैं। आम आदमी भी कुचला जा रहा है। ऐसे मध्यस्थ की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता क्या होगी? इसके अलावा, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, यह हाल ही में किसी एजेंसी ने निष्कर्ष दिया है। पाकिस्तान कंगाल, भूखा, कटोरे वाला देश है। वहां 45 फीसदी से अधिक मुद्रास्फीति है, जो एक रिकॉर्ड है। मिट्टी के तेल की कीमत 433.40 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। पाकिस्तान 1958 से आज तक 26 बार आईएमएफ के पास जा चुका है। ऐसी स्थिति में उसे मध्यस्थता के लिए चुनना संभव नहीं है।

जनरल नॉलेज

बस्तर में माओवादियों से मिला 11 करोड़ का सोना, क्या इसे बेच सकती है सरकार?

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ जंग अब केवल गोलियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उनके खजाने पर भी जोरदार प्रहार किया गया है. माओवादी इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी में सुरक्षाबलों के हाथ करोड़ों का सोना और कैश लगा है. बस्तर के जंगलों में छिपाकर रखा गया यह 11 करोड़ का सोना अब सरकारी खजाने का हिस्सा बनेगा या नहीं, इसे लेकर कानूनी प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं. आइए जानते हैं.

माओवादी इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी - छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पूना मारगेम अभियान के तहत माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण के साथ ही सुरक्षाबलों ने एक ऐसी बरामदगी की है, जिसने सबको चौंका दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह माओवादी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय रिकवरी है. जवानों ने नक्सलियों के पास से कुल 14 करोड़ 6 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है. इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि नक्सली संगठन केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि अवैध वसूली के दम पर अपना साम्राज्य फैला रहे थे.

क्या सरकार बेच सकती है यह सोना? - इस बड़ी बरामदगी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस 11 करोड़ के सोने को बेच सकती है? कानूनी जानकारों और रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंटी-नक्सल ऑपरेशंस के दौरान जब्त किया गया सोना और अन्य कीमती सामान राज्य की संपत्ति माना जाता है. हालांकि, इसे सीधे नहीं बेचा जा सकता है. इसकी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है. पुलिस या एनआईए (NIA) जैसी एजेंसियां पहले इन संपत्तियों को जब्त करती हैं और अदालत में यह साबित करती हैं कि यह पैसा या सोना अवैध उगाही और आतंकी गतिविधियों के लिए इकट्ठा किया गया था.

जब्ती और नीलामी की कानूनी प्रक्रिया - एक बार जब कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं और कोर्ट यह मान लेता है कि यह संपत्ति अवैध है, तो इसे आधिकारिक तौर पर कॉन्फिस्केट यानी कुर्क कर लिया जाता है. इसके बाद सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह इस सोने को सरकारी खजाने में जमा कर दे या फिर इसकी नीलामी करके इसे बेच दे. इस प्रक्रिया से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अक्सर नक्सल विरोधी अभियानों को फंड करने, सुरक्षाबलों के आधुनिकीकरण या आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों के पुनर्वास के लिए किया जाता है.

नक्सलियों की वित्तीय कमर पर चोट - सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोने की बरामदगी नक्सलियों के वित्तीय तंत्र के लिए एक घातक प्रहार है. नक्सली संगठन अक्सर व्यापारियों और ठेकेदारों से उगाही गई रकम को सोने में बदल देते हैं. सोना छिपाने में आसान होता है और समय के साथ इसकी कीमत भी बढ़ती है. मार्च और अप्रैल 2026 में हुई इन बड़ी बरामदगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षाबलों की रणनीति अब नक्सलियों की रसद और पैसे की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट देने की है.

टेक्नोलॉजी

डेस्कटॉप पर Google Chrome चला रहे हैं? हो जाइए सावधान, सरकार की चेतावनी, खतरे में है आपका डेटा, तुरंत करें ये काम

अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर Google Chrome का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने हाल ही में एक गंभीर चेतावनी जारी की है जिसमें Chrome के डेस्कटॉप वर्जन में खतरनाक खामियों का खुलासा हुआ है. इस चेतावनी को हाई सीवेरिटी कैटेगरी में रखा गया है यानी इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा.

किन यूजर्स पर है सबसे ज्यादा खतरा? - एजेंसी के अनुसार, यह समस्या उन यूजर्स को प्रभावित कर सकती है जो Chrome का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. खासतौर पर Windows, macOS और Linux प्लेटफॉर्म पर चल रहे पुराने ब्राउजर वर्जन जोखिम में हैं. अगर आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो आप अनजाने में साइबर हमले का शिकार बन सकते हैं.

कैसे काम करता है यह साइबर अटैक? - 0सबसे चिंताजनक बात यह है कि हैकर्स को आपके सिस्टम तक पहुंचने के लिए किसी फिजिकल एक्सेस की जरूरत नहीं होती. वे सिर्फ आपको किसी खतरनाक या फर्जी वेबसाइट पर

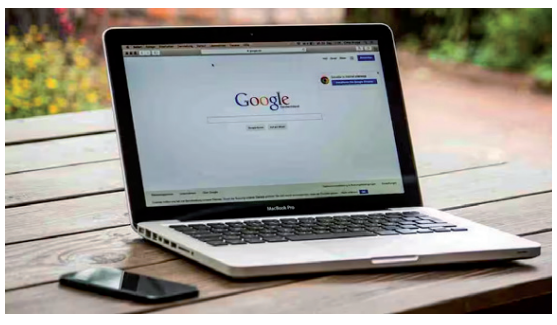

क्लिक करने के लिए उकसा सकते हैं. जैसे ही आप उस पेज को खोलते हैं, बैकग्राउंड में छिपी खामियां एक्टिव हो सकती हैं और हमला शुरू हो सकता है.

इन कमजोरियों में कई तकनीकी समस्याएं शामिल हैं जो ब्राउजर के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद हैं. आसान भाषा में समझें तो ये ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर कोई भी व्यक्ति आपके सिस्टम पर अपनी मर्जी से कोड चला सकता है.

क्या हो सकता है नुकसान? - अगर इन खामियों का गलत इस्तेमाल किया गया तो हैकर्स आपके डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं या फिर आपके सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा, आपके डिवाइस को क्रैश करना या सेवाओं को बाधित करना भी संभव है. यह खतरा सिर्फ व्यक्तिगत यूजर्स तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनियों और ऑफिस सिस्टम्स के लिए भी उतना ही गंभीर है.

बचाव का आसान तरीका क्या है? - अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान काफी आसान है. आपको बस अपने Google Chrome ब्राउजर को तुरंत लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना है. कंपनी ने इन खामियों को ठीक करने के लिए पहले ही अपडेट जारी कर दिया है और CERT-In ने भी बिना देरी किए अपडेट करने की सलाह दी है.

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में वर्क वीजा नियमों में बड़ा बदलाव

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने फॉर्म आई-129 से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी

होंगे। इस बदलाव के बाद, अगर कोई आवेदन पुराने फॉर्म (01/20/25 एडिशन) में भेजा जाता है, तो विभाग उसे स्वीकार नहीं करेगा। फॉर्म आई-129 का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों के लिए करती हैं। यह फॉर्म उन लोगों के लिए भरा जाता है जो अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने या ट्रेनिंग लेने आते हैं। इसमें कई गैर-आप्रवासी वीजा शामिल हैं। फॉर्म आई-129 के नए एडिशन में वित्त वर्ष 2027 के II-1बी कैप सीजन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब यह नई वेतन-आधारित लॉटरी प्रणाली के तहत काम करेगा। नए फॉर्म में नियोक्ताओं को नौकरी के लिए जरूरी न्यूनतम शिक्षा की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही पढ़ाई का सटीक विषय, न्यूनतम अनुभव की जरूरत और यह भी बताना होगा कि क्या उस पद पर सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां शामिल हैं। ये वही जानकारियां हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी श्रम विभाग वेतन का स्तर (लेवल I से लेवल IV) तय करने के लिए करता है। अब संशोधित फॉर्म आई-129 में वेतन के दो स्तर दिखाई देंगे: यूएससीआईएस ने 27 फरवरी 2026 को फॉर्म आई-129 का नया एडिशन (02/27/26) जारी किया है। 1 अप्रैल 2026 से केवल इसी नए एडिशन को स्वीकार किया जाएगा। तब तक पुराने फॉर्म (01/20/25 एडिशन) का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिशन की तारीख फॉर्म और निर्देशों वाले पेज के नीचे दी गई होती है। 31 मार्च 2026 तक मिलने वाले पुराने फॉर्म (01/20/25 एडिशन) स्वीकार किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद मिलने वाले पुराने फॉर्म को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कंपनियों को अब नए नियमों के हिसाब से ही आवेदन तैयार करने होंगे ताकि उनके कर्मचारियों के वीजा आवेदन रद्द न हों।

इस्राइलियों की हत्या के दोषी फलस्तीनियों को मिलेगी मौत की सजा

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल में एक बड़ा और विवादित फैसला सामने आया है। देश की संसद नेसेट ने सोमवार को एक ऐसा कानून पास किया है, जिसमें इस्राइलियों की हत्या के दोषी पाए जाने वाले फलस्तीनियों के लिए मौत

की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत, अगर वेस्ट बैंक के किसी फलस्तीनी को राष्ट्रवादी वजह से हत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसे फांसी दी जा सकती है। यानी ऐसे मामलों में मौत की सजा अब मुख्य सजा होगी। बता दें कि इस बिल को पास कराने में इस्राइल के दक्षिणपंथी नेताओं की बड़ी भूमिका रही। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद संसद में मौजूद रहे और उन्होंने इस कानून के समर्थन में वोट दिया। हालांकि, यह कानून सिर्फ आगे होने वाले मामलों पर लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं। साथ ही अदालतों के पास यह अधिकार भी रहेगा कि वे चाहें तो उम्रकैद की सजा भी दे सकती हैं, यहां तक कि इस्राइली नागरिकों के मामलों में भी। गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक ओर इस्राइल में इस कानून को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है। दूसरी ओर इस फैसले की कई मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण, बेहद कठोर (सख्त) है और इससे हिंसा रुकने की संभावना भी कम है। वहीं फलस्तीनी संगठनों ने भी इसे अन्यायपूर्ण बताया है। हालांकि मामले में अब माना जा रहा है कि इस कानून को इस्राइल की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

पत्रकारों से बदसलूकी पर इस्राइली सेना की कार्रवाई

बटालियन निलंबित; सेनाध्यक्ष ने जताया खेद

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने वेस्ट बैंक के जुडिया और सामरिया इलाके में पत्रकारों के साथ अपने सैनिकों के गलत व्यवहार को स्वीकार किया है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की अगुवाई में हुई एक आंतरिक जांच के बाद सेना ने यह कदम उठाया है। यह मामला 'एरिया ए' में एक अवैध चौकी को खाली कराने के अभियान से जुड़ा है। इस्राइली सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने पत्रकारों के प्रति सैनिकों के आचरण की जांच पूरी कर ली है। जांच में पाया गया कि पत्रकारों के साथ व्यवहार के दौरान सैनिकों से कई गलतियां हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, सैनिकों के व्यवहार के तरीके में कमियां थीं और उन्होंने सेना के आदेशों का उल्लंघन किया। सैनिकों ने प्रेस के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए तय किए गए नियमों का पालन नहीं किया। जांच के नतीजों से पता चला कि उस

इलाके में तैनात सैनिकों ने सैन्य प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया। ऑपरेशन वाले क्षेत्रों में पत्रकारों के साथ कैसे पेश आना है, इसके लिए बने नियमों को तोड़ा गया। इन गलतियों ने यूनिट के अनुशासन और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन कमियों को देखते हुए इस्राइली सेना ने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की है। सेना ने उस इलाके में तैनात बटालियन के ऑपरेशनल तैनाती को तुरंत निलंबित कर दिया है। सेना ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह प्रेस की आजादी का सम्मान करती है और उसे बढ़ावा देती है। सेना ने इस घटना पर गहरा खेद जताया है। यह कदम मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिलाने के लिए उठाया गया है कि सेना प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्य सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने इसे एक गंभीर नैतिक घटना बताया जो सेना के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हर सैनिक भर्ती के समय शपथ लेता है कि हथियारों का इस्तेमाल केवल मिशन को पूरा करने के लिए होगा। हथियारों का इस्तेमाल कभी भी बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि इस्राइली सेना के भीतर ऐसी घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों को खाली कराना हमेशा से एक संवेदनशील और विवादित प्रक्रिया रही है। इन अभियानों के दौरान अक्सर पत्रकार, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां मौजूद रहते हैं।

अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान युद्ध से पैसा बनाने की कोशिश की, रिपोर्ट के दावे पर पेंटागन ने दिया जवाब

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ एक बार फिर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से कुछ सप्ताह पहले पीट हेगसेथ का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रोकर ने रक्षा केंद्रित फंड में निवेश करने की कोशिश की थी। रायटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि एक ब्रोकर, जो

मॉर्गन स्टेनली के साथ काम करता है, उसने फरवरी में दिग्गज निवेशक कंपनी ब्लैकरॉक से संपर्क किया था। ब्रोकर ने ब्लैकरॉक को डिफेंस इंडस्ट्रियल एक्टिव ईटीएफ में निवेश के लिए मनाने की कोशिश की थी। यह ब्रोकर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का भी प्रतिनिधित्व करता है। ब्लैकरॉक का 3.2 अरब डॉलर का इक्विटी फंड उन कंपनियों पर फोकस करता है, जो सरकारी रक्षा खर्च से मिलने वाले फायदे पर फोकस करती हैं। भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति में इ कंपनियों का फायदा और बढ़ जाता है। इन कंपनियों में आरटीएक्स, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ नजदीकी संबंध हैं। हालांकि प्रस्तावित निवेश फाइनल नहीं हो सका।

डेट्रॉइट में यहूदी मंदिर पर हमले का हिजबुल्ला कनेक्शन; एफबीआई बोला

आरोपी ने वीडियो में बताए थे खतरनाक इरादे

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के मिशिगन के डेट्रॉइट इलाके में मार्च की शुरुआत में एक यहूदी मंदिर (सिनेगॉग) पर ट्रक से हुए हमला के मामले में एक बड़ी खबर सामे आ रही है। मामले में अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने सोमवार को बड़ा दावा करते हुए बताया कि हमला करने वाला व्यक्ति अयमान गजाली ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह से प्रेरित था। डेट्रॉइट में एफबीआई की प्रमुख जेनिफर रन्यान ने कहा कि गजाली ने हमले से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी हिंसक मंशा जाहिर की थी। वीडियो में उसने कहा था कि वह जितने ज्यादा लोग मार सके, मारना चाहता है। बता दें कि ये घटना बीते 12 मार्च की है। हमले का शिकार मंदिर 'टेम्पल इस्राइल' है, जो 'रिफॉर्म यहूदी धर्म' का हिस्सा है। यह यहूदी धर्म की सबसे बड़ी शाखा है और सामाजिक न्याय और समानता जैसे मुद्दों पर जोर देती है। मंदिर की स्थापना 1941 में डेट्रॉइट में हुई थी। 1980 के दशक में इसे वेस्ट ब्लूमफील्ड में ले जाया गया। अब इसके 12,000 से अधिक सदस्य हैं।

अब समझिए पूरा घटना क्रम

एफबीआई के अनुसार डियरबॉर्न हाइट्स में रहने वाला गजाली मंदिर की पार्किंग में कुछ घंटों तक रुका रहा। इसके बाद उसने बंद दरवाजों को तोड़कर अपना पिकअप ट्रक मंदिर के अंदर घुसा दिया। ट्रक बच्चों के कक्षा वाले वाले हिस्से में पहुंच गया और वहां एक सुरक्षा गार्ड को टक्कर मार दी। उसके बाद गजाली ने एक और सुरक्षा गार्ड के साथ गोलीबारी की और अंत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हमले के समय ट्रक में आग लग गई थी और उसमें कई पेट्रोल के डिब्बे और बड़े पटाखे रखे हुए

थे। गजाली की पत्नी ने पहले दी थी चेतावनी

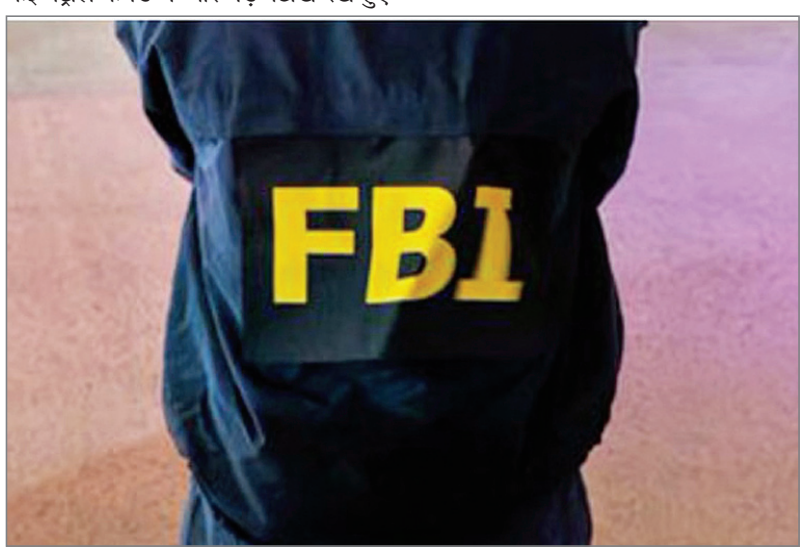

हालांकि गनीमत रही कि मंदिर में मौजूद 150 बच्चों और कर्मचारियों में किसी को चोट नहीं आई। बचाव दल ने तुरंत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूसरी ओर 911 कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि हमले से पहले गजाली की पहली पत्नी ने पुलिस को फोन करके चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि वह बहुत परेशान है और खुदकुशी कर सकता है। उसकी मानसिक हालत इसलिए बिगड़ी थी, क्योंकि लेबनान में इस्राइल की बमबारी में उसके कई परिवार के सदस्य मारे गए थे।

हिजबुल्ला का कमांडर था गजाली का भाई

दूसरी ओर दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि गजाली का भाई इब्राहिम गजाली लेबनान में हिजबुल्ला का कमांडर था। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि गजाली के परिवार का हिजबुल्ला से संबंध था। गौरतलब है कि हिजबुल्ला 1982 में लेबनान में बना था। इसका मुख्य मकसद शुरू में दक्षिणी लेबनान पर इस्राइल के कब्ज़े को खत्म करना था। हालांकि अब यह पूरी तरह से इस्राइल को खत्म करना चाहता है। अमेरिका ने इसे कई वर्षों से आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हिजबुल्ला एक राजनीतिक दल भी है और इसके सदस्य लेबनान की संसद में हैं।

सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक है वेपिंग का शौक, नई रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सिडनी, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि वेपिंग (ई-सिगरेट) सिगरेट पीने से ज़्यादा सुरक्षित नहीं है और इससे फेफड़ों के साथ-साथ मुंह का कैंसर भी हो सकता है।

इंटरनेशनल डेस्कः ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि वेपिंग (ई-सिगरेट) सिगरेट पीने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है और इससे फेफड़ों के साथ-साथ मुंह का कैंसर भी हो सकता है। सिडनी की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने 2017 और 2025 के बीच पब्लिश हुई साइंटिफिक स्टडीज का रिव्यू करने के बाद यह नतीजा निकाला है।

रिसर्च की सबसे चिंताजनक बातों में से एक यह है कि वेपिंग से यूजर के डीएनए में बदलाव हो सकते हैं, जिससे सेल में खराबी आ सकती है, जो सीधे कैंसर से जुड़ा है। यह सांस की नली के टिशू को नुकसान पहुंचाता है और मुंह के माइक्रोबायोम को बदलता है, जिससे सूजन और मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

जो लोग पारंपरिक सिगरेट पीते हैं और वेप भी करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे लोगों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा चार गुना ज्यादा पाया गया है। स्टडी के मुख्य लेखक, प्रोफेसर बर्नार्ड स्टीवर्ट ने साफ किया कि वेपिंग सुरक्षित होने के मामले में किसी भी चीज का विकल्प नहीं है; यह खतरनाक है।

युवाओं पर बुरा असर

रिपोर्ट में एक 19 साल के नौजवान का मामला बताया गया है, जिसे वेपिंग की हिस्ट्री की वजह से गंभीर ओरल कैंसर हो गया, जो आमतौर पर इस उम्र में बहुत कम होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हालांकि वेप में सिगरेट की तरह टार नहीं होता, लेकिन इसमें फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जहरीले केमिकल होते हैं जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डीएनए में बदलाव लाते हैं।

प्रोफेसर फ्रेडी सिटास ने कहा कि यह मानना पूरी तरह से गलत है कि वेपिंग सेफ है। उन्होंने इसकी तुलना इस बात से की कि चाकू मशीन गन से कम खतरनाक होते हैं क्योंकि वे एक बार में कम लोगों को मार सकते हैं और चेतावनी दी कि हमें सिगरेट के नुकसान की तरह सबूत जमा होने के लिए 100 साल तक इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अभी से कड़े कदम उठाने चाहिए। ब्रिटेन जैसे देश अभी युवाओं में वेपिंग के बढ़ते चलन को रोकने के लिए डिस्पोजेबल वेप्स पर बैन लगाने जैसे कदम उठा रहे हैं। रिसर्चर्स ने सलाह दी है कि वेपिंग को स्मोकिंग छोड़ने के सेफ तरीके के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

पश्चिम एशिया में तनाव: इराक में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला; तेल-ऊर्जा के बाद शिक्षा संस्थान जंग का नया मोर्चा

बगदाद, एजेंसी। प्रेस टीवी के अनुसार, इराक के सुलेमानिया में स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक, सुलेमानी पर मंगलवार सुबह हमला किया गया। हालांकि, इस घटना पर अब तक यूनाइटेड स्टेट्स और इस्राइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका-इस्राइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसकी यूनिवर्सिटियों और वैज्ञानिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक, ईरान के विज्ञान और स्वास्थ्य मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर अमेरिका और इज़राइल की कड़ी आलोचना की है। बयान में कहा गया कि मार्च 2026 से कई विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों पर हमले हुए हैं। इनमें ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिराज यूनिवर्सिटी की फार्मेसी फैकल्टी, इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी और उर्मिया यूनिवर्सिटी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क शामिल हैं। इन हमलों में शिक्षा और रिसर्च ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई शिक्षकों और

शोधकर्ताओं की जान भी गई है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की वैज्ञानिक नींव और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना है। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (ढ्ढक्रत्रष्ट) ने 29 मार्च को अमेरिका को अल्टीमेटम जारी किया था। इसमें मांग की गई थी कि ईरान की यूनिवर्सिटियों पर हुए हमलों की निंदा की जाए।

भारत आने वाले ईरानी विमान पर अमेरिका का हमला

तेहरान ने कड़ी निंदा की; मानवीय मिशन बाधित

तेहरान, एजेंसी। ईरान भारत के लिए उड़ान भर रहे मानवता मिशन विमान पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद आगबबूला है। घटना के बाद ईरान ने इसे युद्ध अपराध करार दिया और अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रिपोर्टों के अनुसार, महान एयर का यह विमान ईरान के मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। यह विमान मानवीय सहायता मिशन के लिए नई दिल्ली आने वाला था, जहां से उसे राहत सामग्री ले जानी थी। हमले से विमान क्षतिग्रस्त हो गया और पूर्व नियोजित मानवीय सहायता मिशन बाधित हो गया।

भारत में ईरानी दूतावास ने कहा कि सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार, मानवीय मिशनों में लगे नागरिक विमानों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूतावास ने लिखा दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों को ले जा रहे इस ईरानी विमान पर हमला करना युद्ध अपराध है। ईरानी दूतावास ने बताया कि शिकागो कन्वेंशन (1944) और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1971) के तहत, नागरिक विमानों पर हमले अंतरराष्ट्रीय अपराध माने जाते हैं। इसके अलावा जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल ढ्ढ, अनुच्छेद 52 के अनुसार, नागरिक वस्तुओं पर हमले, जिनमें मानवतावादी सहायता विमान भी शामिल हैं, युद्ध अपराध में आते हैं। दूतावास ने अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

1 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचना था विमान: बताया जा रहा है कि यह विमान 1 अप्रैल सुबह 4:00 बजे पहुंचने वाला था। इस

घटना के बाद देश में नागरिक उड्डयन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बता दें कि, महान एयर एक निजी स्वामित्व वाली ईरानी एयरलाइन है जो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों में उड़ानें संचालित करती है।

क्षतिग्रस्त हुए विमान को भारत से दवाइयों सहित 11 टन मानवीय सहायता ईरान ले जानी थी। पहले की खेपों में भारतीय उड़ानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ईरान के लिए भारत की पहली सहायता खेप 18 मार्च 2026 को भेजी गई थी। तब भारत ने कहा था कि यह सहायता दोनों देशों के बीच दोस्ती और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।

संघर्ष के बीच बड़ी तैयारी में ट्रंप, समझिए कैसे ईरान की बढ़ गई मुश्किलें

वॉशिंगटन, एजेंसी। पश्चिम एशिया में एक महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी रणनीति सामने आई है। जारी हमलों के बीच अब ट्रंप प्रशासन होर्मुज की खाड़ी पर अपना नियंत्रण वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दी। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में बेसेंट ने कहा कि जल्द ही या तो अमेरिकी जहाजों या कई देशों के संयुक्त जहाजों के जरिए अमेरिका का नियंत्रण होर्मुज जलडमरूमध्य पर होगा। बेसेंट ने आगे बताया कि फिलहाल कुछ देश ईरान के साथ समझौते करके अपने जहाजों को जलडमरूमध्य पार करा रहे हैं। लेकिन समय के साथ अमेरिका इसे पूरी तरह नियंत्रित करेगा और वहां जहाजों को सुरक्षित रूप से गुजरने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि बाजार में तेल की आपूर्ति अच्छी है और रोजाना कई जहाज़ जलडमरूमध्य से गुजर रहे हैं। लेकिन अंततः अमेरिका इस रास्ते पर फिर से नियंत्रण स्थापित करेगा।

होर्मुज को लेकर वैश्विक चिंताएं: बेसेंट का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते होर्मुज

जलडमरूमध्य को लेकर वैश्विक चिंता सातवें आसमान पर पहुंच गई है। इसका कारण है कि होर्मुज दुनिया के तेल प्रवाह का एक अहम मार्ग है और यह लगभग विश्व के एक पांचवें हिस्से के तेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह योजना वैश्विक समुद्री और तेल बाजारों पर बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है।

रुबियो बोले- ईरान की नौसेना और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर रहे: दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एबीसी न्यूज को बताया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और रक्षा उद्योग को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को हमेशा के लिए खाड़ी पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे और अमेरिका अपने उद्देश्यों को कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेगा। रूबियो ने कहा कि हम ईरान की नौसेना और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर रहे हैं और उनके रक्षा उद्योग को भी कमजोर कर रहे हैं, ताकि वे भविष्य में नए मिसाइल या ड्रोन न बना सकें।

ईरान की धमकियों पर बिफरे रुबियो: रुबियो ने खाड़ी के नियंत्रण पर ईरान की धमकियों पर भी चेतावनी दी। रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास कई विकल्प मौजूद हैं और अगर ईरान खाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। हालांकि ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगहेई ने कहा कि अमेरिका की बातचीत और कूटनीति की बातें विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार-बार अपनी स्थिति बदलता रहा है, जबकि ईरान ने हमेशा स्पष्ट रुख अपनाया है।

पाकिस्तान की बातचीत बैठक से ईरान ने बनाई दूरी

ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान के शाहीबाज शरीफ द्वारा आयोजित चार देशों की बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया। इन घटनाओं के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ और हॉर्मुज की खाड़ी खुली नहीं तो अमेरिका ईरान के बिजली प्लांट, तेल कुओं और खार्ग द्वीप को नष्ट कर देगा। गौरतलब है कि ये बयानबाजी और धमकियों की घटनाएं ऐसे समय पर सामने आई हैं जब अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है।

टीम इंडिया टी20 सीरीज के लिए जुलाई में करेगी जिम्बाब्वे का दौरा, जारी हुआ शेड्यूल

नई दिल्ली, एजेंसी | बीसीसीआई ने बुधवार, 1 अप्रैल को टीम इंडिया के जिम्बाब्वे दौरे के शेड्यूल का ऐलान किया। टीम इंडिया इस साल जुलाई में 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी। सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई को होगी जबकि तीसरा और आखिरी मैच 26 जुलाई को होगा। टीम इंडिया ने इससे पहले 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां उसने 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जिम्बाब्वे दौरे के शेड्यूल का ऐलान किया। इस दौरे पर तीनों ही टी20 इंटरनेशनल मैच हरारे में ही खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा।

वहीं जिम्बाब्वे टीम भी अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेगी। जहां जनवरी 2027 में भारत तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगा। उ सीरीज का पहला मैच कोलकाता में, दूसरा हैदराबाद और तीसरा मुंबई में खेला जाएगा।

26 रन पर गिरे 4 विकेट, फिर समीर रिजवी-ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने किया चमत्कार; दिल्ली को 6 विकेट से मिली जीत

नई दिल्ली, एजेंसी | आईपीएल 2026 के पांचवें लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया. समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 119* (76गेंद) रनों की साझेदारी की. टीम के लिए समीर रिजवी ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 70* रन स्कोर किए. इस दौरान लखनऊ के लिए प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए.

मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए उतरी लखनऊ की टीम 18.4 ओवर में 141 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए अब्दुल समद ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में 36 रन बनाए. इस दौरान दिल्ली के लिए लुंगी एंडिगी और टी नटराजन ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट अपने खाते में डाले. रन चेज में दिल्ली ने 17.1 ओवर में जीत हासिल कर ली. दिल्ली को यह जीत तब मिली जब उन्होंने 26 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

रन चेज के शुरुआत में फंसी दिल्ली -

रन चेज करते हुए दिल्ली की टीम शुरुआत में फंसती हुई नजर आई. पावरप्ले में टीम ने सिर्फ 33 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए थे. इस दौरान टीम के लिए केएल राहुल (00), नितीश राणा (15), पथुम निसांका (01) और अक्षर पटेल (00) पवेलियन लौट चुके थे. यहां से टीम की जीत बहुत मुश्किल लगने लगी थी.

जल्दी 4 विकेट गिर जाने के बाद समीर रिज्वी और ट्रिस्टन स्टब्स ने पांचवें विकेट के लिए साझेदारी करना शुरू की. दोनों ने बखूबी मिलकर पारी को संभाला. पारी बढ़ने के साथ दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और धीरे-धीरे टीम को जीत की लाइन पार करवा दी.

लखनऊ की गेंदबाजी

लखनऊ के लिए प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा विकेट अपने खाते में डाले. इस दौरान उन्होंने 3 ओवर में 20 रन खर्चे. इसके अलावा मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. शमी ने 4 ओवर में 28 रन और मोहसिन ने 4 ओवर में 19 रन खर्चे.

दूध बेचने से लेकर गोल्ड मेडल जीतने तक : जम्मू कश्मीर के पहलवान हमाम हुसैन का सपना हुआ सच

नई दिल्ली, एजेंसी | करीब एक दशक तक मिट्टी के अखाड़ों पर खेलने से लेकर परिवार की मदद के लिये दूध बेचने तक जम्मू कश्मीर के पहलवान हमाम हुसैन की कड़ी मेहनत खेलो इंडिया ट्राइबल खेलों में रंग लाई जहां राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। जम्मू के जोरावर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय हमाम के पिता का पांच साल पहले निधन हो गया था जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके और उनके बड़े भाई के कंधों पर आ गई।

दोनों ने मिलकर दूध बेचकर घर चलाया और इसी के साथ हमाम ने अपने कुश्ती के सपने को जिंदा रखा। यह संघर्ष आखिरकार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में रंग लाया, जहां हमाम ने पुरुषों के 79 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में हिमाचल प्रदेश के मोहित कुमार को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह उनके 14 साल के कुश्ती करियर का पहला राष्ट्रीय स्तर का स्वर्ण पदक है।

हमाम ने साई मीडिया से कहा, "मेरे बड़े भाई भी पहलवान थे और राज्य स्तर पर खेल चुके हैं। पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी हम पर आ गई।

मेरे भाई को कुश्ती छोड़नी पड़ीऔर उन्होंने दूध बेचना शुरू कर दिया। मैं भी उनके साथ दूध देने जाता था क्योंकि परिवार चलाना जरूरी था।लेकिन मेरे भाई ने मुझे हमेशा कुश्ती जारी रखने के लिए प्रेरित किया और मुझे दंगलों में लेकर जाते थे।"

आईपीएल बोरिंग और मनीलेस है.., आईपीएल छोड़ पीएसएल में खेलना, एडम जैम्पा ने जाहिर की अपनी हताशा

नई दिल्ली, एजेंसी | कई समय तक आईपीएल में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जैम्पा को अब आईपीएल बोरिंग और मनीलेस लगने लगा है। पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल से बेहतर बता दिया। पाकिस्तान ने अब बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी हैं। जलन के मारे पाकिस्तान अब अपनी लीग के प्रमोशन के लिए नए हथकंडे अपना रहा है। इसी प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने एडम जैम्पा से बेतुका बयान दिलाया है। जैम्पा ने एक के हवाले से बयान दिलवाया है कि भारत में प्रतिभा के अनुसार पैसे नहीं मिलते हैं।

दरअसल, पीएसएल आजकल किसी ना किसी कारण चर्चा में है। पहले विदेशी खिलाड़ियों ने निजी कारणों से लीग में खेलने से मना कर दिया। फिर कुछ विदेशी खिलाड़ी जो वहां पहुंचे थे उन्होंने बीच में ही टूर्नामेंट छोड़ दिया और आईपीएल से जुड़ गए। इसके साथ ही कमेंटेटर निक नाइट भी आईपीएळ कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पीएसएल से किनारा कर बैठे।

इस साल पीएसएल बंद

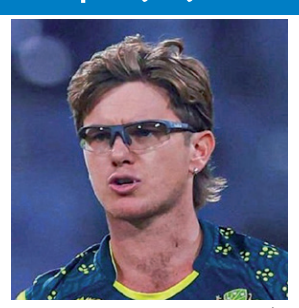

दरवाजों के पीछे खेला जा रहा है। ऐसे में लीग को फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। तमात विवादों के बाद पाकिस्तान ने अपनी लीग को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोपेगेंडा अपनाया और आईपीएल को नीचा दिखाने की कोशिश की। हालांकि, अब वह इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए हैं।

एडम जैम्पा ने जो बयान दिया है उससे वह खुद ही विवादों में आ गए हैं। जैम्पा ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल एआरवाई के पॉडकास्ट में कहा कि, मैंने इस साल आईपीएल से नाम वापस ले लिया। सच कहूं तो मेरी स्किल सेट वाले खिलाड़ी को वहां उतनी रकम नहीं मिलती, जितनी कुछ अन्य तरह के खिलाड़ियों को मिलती है। आईपीएल जितना समय लेता है उसे देखते हुए मेरे लिए इसे खेलना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं लगा। जैम्पा इस बयान के बाद फंस गए हैं।

पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए जाने के बाद जैम्पा ने आईपीएल के रजिस्टर नहीं करवाया। उन्होंने पीएसएल के लिए अपना नाम दिया था। उन्हें कराची किंग्स ने उनके बेस प्राइस 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में साइन किया था। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये यानी 1.51 करोड़ भारतीय रुपये।

व्यापार

मार्च में जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये के पार, सरकार की तिजोरी में जमा हुए 22.27 लाख करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी | देश में जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में सकल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 2,00,064 करोड़ रुपये हो गया, जो मार्च 2025 के 1,83,845 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.8% अधिक है।

जीएसटी संग्रह बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 20.55 लाख करोड़ रुपये से 8.3% ज्यादा है। यह आंकड़े टैक्स कलेक्शन में लगातार बने हुए मजबूत रुझान को दर्शाते हैं। मार्च में दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना साल के अंत में बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत माना

जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, घरेलू जीएसटी राजस्व मार्च में 5.9% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो देश के भीतर स्थिर खपत को दर्शाता है। वहीं, आयात से जुड़े जीएसटी कलेक्शन में 17.8% की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ती आयात गतिविधियों और बेहतर कस्टम्स कलेक्शन की ओर इशारा करती है।

आयात में हुई वृद्धि से आईसीएसटी संग्रह बढ़ा

आयात में भारी वृद्धि के चलते मार्च में आईजीएसटी संग्रह बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी संग्रह में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो केंद्र और राज्य कर घटकों में संतुलित वृद्धि को दर्शाती है।

जीएसटी रिफंड में हुई 13.8% की वृद्धि

मार्च में कुल जीएसटी रिफंड में सालाना आधार पर 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 22,074 करोड़ रुपये हो गया। रिफंड को समायोजित करने के बाद, शुद्ध जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2026 के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह 19.34 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है, जो उच्च धनवापसी के बावजूद लगातार राजस्व वृद्धि को दर्शाता है।

एसजीएसटी को लेकर क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र (+17%), कर्नाटक (+14%) और तेलंगाना (+19%) जैसे कई बड़े राज्यों में मार्च में एसजीएसटी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु (-8%) और असम (-15%) जैसे कुछ राज्यों में गिरावट देखी गई।

एलआईसी को 3750 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया मामला

नई दिल्ली, एजेंसी | केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। यह मामला भारतीय जीवन बीमा निगम को कथित तौर पर 3,750 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। यह जांच ऐसे समय में शुरू हुई है जब अनिल अंबानी पहले से ही कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ भारी धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

क्या है एलआईसी का आरोप? - अधिकारियों के बयान के अनुसार, यह नया मामला एलआईसी की ओर से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। इसमें साजिश, धोखाधड़ी, पैसों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिसंपत्ति कवर के बारे में झूठे दावे किए। इन भ्रामक जानकारियों के आधार पर एलआईसी को 4,500 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदने के लिए धोखे से प्रेरित किया गया।

फोरेंसिक ऑडिट में हुए चौंकाने वाले खुलासेः - एलआईसी की यह शिकायत बीडीओ इंडिया एलएलपी की ओर से 15 अक्तूबर, 2020 को की गई एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय संचालन में कई गंभीर गड़बड़ियों को उजागर किया गया है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए धन का दुरुपयोग किया गया और सहायक कंपनियों के माध्यम से इसकी हेराफेरी की गई।

शेल संस्थाओं और इंटर-कंपनी डिपॉजिट्स के जरिए धन को सुनियोजित तरीके से बाहर निकाला गया।

फर्जी बिलों की छूट, फर्जी देनदारों का निर्माण और फिर उन्हें बट्टे खाते में डालने जैसे कदम उठाए गए।

सुरक्षा परिसंपत्तियों को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, जिससे कंपनी की संपत्ति और उन पर लगाए गए प्रभार के बीच भारी अंतर पैदा हो गया।

बैंकिंग सेक्टर पर इस मामले का क्या असर? - इस पूरे मामले का प्रभाव केवल एलआईसी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का व्यापक बैंकिंग सेक्टर भी इसके दायरे में है। सीबीआई ने इससे पहले आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 11 बैंकों के उस कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक है, जिसने अनिल अंबानी समूह को कर्ज दिया था। 2013-17 के दौरान समूह की संस्थाओं के बीच जटिल लेन-देन के जरिए लोन फंड्स का डायवर्जन किया गया। 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 19,694.33 करोड़ रुपये के एक्सपोजर में से अकेले एसबीआई को 2,929.05 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था। इसी मामले में एसबीआई की शिकायत के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2025 को एक एफआईआर दर्ज की थी।

कानूनी कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ रही है? - मामले की जांच अभी प्रगति पर है। 2,929.05 करोड़ रुपये के एसबीआई धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में अनिल अंबानी से सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय में लगातार दो दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है।

दो हजार रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक का बड़ा खुलासा, तीन वर्ष पहले वापस लेने का हुआ था एलान

नई दिल्ली, एजेंसी | चलन से वापस लिए गए दो हजार रुपये के कुल नोटों में से 98.45 फीसदी नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च, 2026 को कारोबार बंद होने तक घटकर 5,501 करोड़ रुपये रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अभी चलन में 2000 रुपये के कितने नोट?

आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 तक चलन में रहे दो हजार रुपये के नोटों का 98.45 फीसदी हिस्सा अब तक वापस आ चुका है। यह आंकड़ा नोट वापसी अभियान की सफलता को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया

है कि दो हजार रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। नोटों की वापसी की घोषणा के बाद से, आरबीआई ने विभिन्न माध्यमों से जनता को नोट बदलने और जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के प्रचलन को कम करना है। 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने पर चलन में दो हजार रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था। यह मूल्य 31 मार्च, 2026 को कारोबार बंद होने तक काफी कम होकर केवल 5,501 करोड़ रुपये रह गया है। इस भारी गिरावट से पता चलता है कि अधिकांश नोट सफलतापूर्वक वापस ले लिए गए हैं।

कब हुआ था 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का एलान?

दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय 19 मई, 2023 को लिया गया था। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों के प्रवाह को विनियमित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। आरबीआई ने इस प्रक्रिया को सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की थी। इस घोषणा के बाद, जनता को अपने पास मौजूद इन नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलने का पर्याप्त अवसर दिया गया। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की गई ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

नोटों को बदलने या जमा करने की क्या है प्रक्रिया?

आरबीआई ने नोटों के विनिमय और जमा के लिए कई सुविधाजनक तरीके प्रदान किए हैं। 19 मई, 2023 से ही आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में दो हजार रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा उपलब्ध है। नौ अक्टूबर, 2023 से इन कार्यालयों में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अपने बैंक खातों में दो हजार रुपये के नोट सीधे जमा करने की सुविधा भी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, आम जनता देश के किसी भी डाकघर से इंडिया पोस्ट के माध्यम से दो हजार रुपये के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकती है। इन विभिन्न सुविधाओं का उद्देश्य नोट वापसी प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ और आसान बनाना है।

क्या 2000 रुपय के नोट अब भी वैध मुद्रा हैं?

आरबीआई ने बार-बार यह दोहराया है कि दो हजार रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि इन नोटों को किसी भी लेनदेन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने लोगों से इन नोटों को जल्द से जल्द बदलने या अपने बैंक खातों में जमा करने का आग्रह किया है। यह कदम नोट वापसी प्रक्रिया को पूरा करने और अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के प्रचलन को कम करने में मदद करेगा। आरबीआई इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नोटों की वापसी सुचारु रूप से हो।

रूसी फिल्म में बॉलीवुड तड़का

डिस्को डांसर से मेलोड्रामा तक रूसी फिल्म 'पर्सिमोन ऑफ माई लव' में दिखेगा बॉलीवुड वाला मसाला

इस साल की शुरुआत ही सिनेमाप्रेमियों के लिए काफी खास था, क्योंकि कई सारी जबरदस्त फिल्में इस साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. उन्हीं में से इन दिनों एक अनोखी फिल्म सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है, जो न तो पूरी तरह बॉलीवुड की है और न ही पूरी तरह विदेशी, लेकिन दोनों का ऐसा कोलैबोरेशन है कि इसने दर्शकों को हैरान भी किया है. हम बात कर रहे हैं फिल्म 'पर्सिमोन ऑफ माई लव' , जो कि रूसी फिल्म है, लेकिन इसमें बॉलीवुड का तड़का भी लगा है.1 अप्रैल, 2026 को फिल्म 'पर्सिमोन ऑफ माई लव' रूस में रिलीज होने वाली है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी फिल्म भारत में शूट की गई है और इसमें बॉलीवुड का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता है. फिल्म में बॉलीवुड के क्लासिक एलिमेंट्स जैसे गाने, डांस, ड्रामा और रंग-बिरंगे विजुअल्स को पूरी तरह अपनाया गया है, यही वजह है कि इसे एक तरह से बॉलीवुड को ट्रिब्यूट और हल्के-फुल्के अंदाज में उसकी पैरोडी भी माना जा रहा है.

इंडिया-रूस का कोलैबोरेशन

'पर्सिमोन ऑफ माई लव' को भारत के कई खूबसूरत शहरों में शूट किया गया है जिसमें मुंबई, उदयपुर और जोधपुर का नाम शामिल है. कमाल की बात है कि फिल्म में कई फेमस बॉलीवुड गानें भी शामिल हैं. इस फिल्म को लोग इंडिया और रूस के कमाल के कोलैबोरेशन के तौर पर देख रहे हैं. फिल्म को मारियस वेसबर्ग ने डायरेक्टर किया है, फिल्म में पूरी तरह से मेलोड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं.

हिंदी गाने भी हैं शामिल

ये फिल्म पूरी तरह से रूसी है, जो कि एक ग्रैंड लेवल पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म की शूटिंग की बात की जाए, तो सेट पर हर दिन 350 से ज्यादा क्रू मेंबर्स ने काम किया है, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों लोग शामिल थे. गानों की बात की जाए, तो इसमें 'डिस्को डांसर' और 'जिमी जिमी आजा आजा' जैसे गानों के ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म की कहानी भी पूरी तरह बॉलीवुड स्टाइल में गढ़ी गई है, जिसमें परिवार, इमोशन, रोमांस और एक्शन का जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी की बात करें, तो ये बचपन में बिछड़े दो भाइयों की कहानी है, जिसमें से एक बड़े होकर ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनता है।

45 की श्वेता तिवारी का साड़ी लुक वायरल फैंस हुए फिदा

टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी हमेशा अपनी खूबसूरती और फिटनेस के चलते चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर जब भी वो अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं, लोग हैरान रह जाते हैं.

श्वेता 45 साल की हैं, लेकिन उन्हें देखकर शायद ही कोई उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा पाए. श्वेता अपनी फिटनेस का खास खयाल रखती हैं. कई बार तो लोग उन्हें उनकी बेटी पलक तिवारी की बड़ी बहन कह देते हैं.

श्वेता तिवारी पिछले कुछ वक्त से साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और फैंस उनके इन लुक्स को खूब पसंद भी कर रहे हैं. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरे शेयर की हैं.

श्वेता इन तस्वीरों में हल्के लाल रंग की साड़ी में नज़र आ रही हैं. उनका देसी लुक सोशल मीडिया पर आते ही छा गया. कुछ ही देर में इस पोस्ट पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और हजारों लाइक्स आ गए. कई लोग कमेंट में उनश्वेता तिवारी छोटे पर्दे पर कसौटी जिंदगी की सीरियल से घर घर में मशहूर हुई थीं. उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज़ में काम किया, लेकिन इस सीरियल में निभाए प्रेरणा के किरदार से लोग उन्हें आज भी पहचानते हैं।

'नाइट ऑफ ऑनर्स' में मोहित सूरी, रमेश सिप्पी समेत कई सितारे सम्मानित

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दिल्ली (ढ्ढस्नस्नष्ठ) के रूप में राजधानी ने सिनेमा, संस्कृति और रचनात्मक ऊर्जा का एक भव्य संगम देखा. भारत मंडपम में आयोजित नाइट ऑफ ऑनर्स समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वैश्विक आयोजन में हिस्सा लिया. इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम में फिल्म निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा, अभिनेता अनुपम खेर, अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, दिव्या दत्ता, अर्जन बाजवा सहित देश-विदेश की अनेक प्रतिष्ठित फ़िल्म हस्तियां उपस्थित रहीं. निर्माता-निर्देशक रमेश सिप्पी को शोले के 50 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया.

समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोहों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया. अभिनेता अनुपम खेर की काव्यात्मक प्रस्तुति और ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केज के संगीत ने कार्यक्रम को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की.

एलजी ने फिल्मकारों को बताया सांस्कृतिक दूत

इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह दिल्ली और भारत को क्रिएटिव इकोनॉमी का वैश्विक केंद्र बनाने की एक दृष्टि है. उन्होंने कहा कि भारतीय मिट्टी में जन्मी कहानी दूर देशों के दिलों को छू सकती है और ऐसे मंच उन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का सेतु बनते हैं. दिल्ली की भूमिका यहां और भी विशेष है.

उन्होंने फिल्मकारों से कहा कि आप सिर्फ रचनाकार नहीं, आप सांस्कृतिक दूत हैं. सिनेमा केवल फ्रेम्स और स्क्रिप्ट्स नहीं, यह साहस है, दृष्टिकोण है, और सच्चाई है. उन्होंने कहा कि आज जिनको सम्मान मिल रहा है आप सभी को हार्दिक बधाई और जिन्हें नहीं मिला, याद रखिए, हर वह कहानी जो दर्शकों तक पहुंची, वह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है.

उपराज्यपाल ने कहा कि यह एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन की नींव रखी है, जो दिल्ली के सांस्कृतिक भविष्य को दिशा देगा और भारत को वैश्विक रचनात्मक मानचित्र पर और सशक्त बनाएगा.इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश का हृदय है, एक ऐसा शहर जो इतिहास और आशाओं दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है. यह फिल्म महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राजधानी की नई सांस्कृतिक पहचान को आकार देने का माध्यम है. सिनेमा में लोगों को जोड़ने, प्रेरित करने और सपनों को साकार करने की अद्भुत शक्ति है. यह मंच नए कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और विशेष रूप से महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि ढ्ढस्नस्नष्ठ दिल्ली को एक वैश्विक सांस्कृतिक और सिनेमाई केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने इस आयोजन को 'ऑरेंज इकोनॉमी' और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त पहल बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव केवल सिनेमा का उत्सव नहीं, बल्कि संवाद, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक जीवंत मंच है, जो दिल्ली को वैश्विक रचनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा.पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित करना नहीं है, बल्कि दिल्ली को क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सिनेमा के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.उन्होंने बताया कि ढ्ढस्नस्नष्ठ में 6 फ़िल्म प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, और मुझे गर्व है यह कहते हुए कि इस फेस्टिवल से निकलने वाली 3 फिल्में आने वाले समय में पूरे देश में देखी जाएंगी. कपिल मिश्रा ने कहा कि फ़िल्म परिदृश्य बदला है।

रुक्मिणी वसंत, का उभरता स्टारडम

अपनी एक्टिंग से पूरे साउथ इंडिया में दर्शकों को लुभा रही हैं

कंटारा फ्रैंचाइज़ी सहित बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होने से उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया, जिससे पूरे इंडिया लेवल पर उनकी पहचान और बढ़ गई। एक गर्वित मिलिट्री बैकग्राउंड से आने वाली रुक्मिणी के पिता, कर्नल वसंत वेणुगोपाल, 2007 में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांति काल के वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस मज़बूत पारिवारिक विरासत ने उनके डिसिप्लिन और डेडिकेशन को बनाया है, जबकि उनकी माँ, सुभाषिनी वसंत ने उनमें कला के लिए गहरी समझ पैदा की।

रुक्मिणी वसंत, जिन्होंने कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और अब अपनी एक्टिंग से पूरे साउथ इंडिया में दर्शकों को लुभा रही हैं, बहुत जल्द ही पूरे इंडिया के सबसे होनहार स्टार्स में से एक बन गई हैं। उन्हें फिल्म सप्त सागरदाचे एलो से बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें खास तौर पर युवाओं के बीच एक मज़बूत फैन फॉलोइंग दिलाई। अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा, वह अपनी ज़मीन से जुड़ी पर्सनैलिटी और अपने काम के प्रति डिसिप्लिन्ड अप्रोच से भी इम्प्रेस करती रहती हैं।

कंटारा फ्रैंचाइज़ी सहित बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होने से उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया, जिससे पूरे इंडिया लेवल पर उनकी पहचान और बढ़ गई। एक गर्वित मिलिट्री बैकग्राउंड से आने वाली रुक्मिणी के पिता, कर्नल वसंत वेणुगोपाल, 2007 में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांति काल के वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस मज़बूत पारिवारिक विरासत ने उनके डिसिप्लिन और डेडिकेशन को बनाया है, जबकि उनकी माँ, सुभाषिनी वसंत ने उनमें कला के लिए गहरी समझ पैदा की।

अभी, रुक्मिणी वसंत की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 7 करोड़ है, और उम्मीद है कि 2026 के आखिर तक फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और दूसरे कामों से यह 10 करोड़ तक बढ़ सकती है। सप्त सागरदाचे एलो की सफलता और पूरे भारत के सिनेमा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बाद, उन्होंने अपनी फीस काफी बढ़ा दी है, और कहा जा रहा है कि वह हर फिल्म के लिए लगभग ?3 करोड़ चार्ज कर रही हैं।

कई हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स के साथ उनका करियर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कंतारा- चैप्टर 1 में एक शानदार रोल निभाया, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। वह यश स्टारर और गीतू मोहनदास डायरेक्टेड टॉक्सिक का भी हिस्सा हैं, जिसमें वह एक अहम रोल निभा रही हैं। इसके अलावा, खबर है कि उन्हें ह्रञ्जक्र-प्रशांत नील के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है, जिसका टाइटल अभी ड्रैगन है।

रुक्मिणी ने तमिल सिनेमा में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिसमें उन्होंने विजय सेतुपति के साथ ऐस और शिवकार्तिकेयन के साथ मदारसी में काम किया है। इन रोल्स ने उन्हें इंडस्ट्रीज़ में एक मज़बूत रेप्युटेशन बनाने में मदद की है। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ से बढ़ते अटेंशन के साथ, वह धीरे-धीरे पूरे भारत में फ़ेवरेट बन रही हैं।

अपने नैचुरल एक्टिंग टैलेंट, शानदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ, रुक्मिणी वसंत को आने वाले सालों में उभरते हुए स्टार्स में से एक माना जा रहा है, और उनके बॉलीवुड में भी एंट्री करने का पोटेंशियल है।

शराब तस्कर चढ़े बैकुंठपुर पुलिस के हत्थे

साधना एक्सप्रेस रीवा,

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,देहात एवं एसडीओपी सिरमौर के मार्गदर्शन में बैकुंठपुर थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा के नेतृत्व में शराब की अवैध तस्करी करने वालों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस के मुताबिक ग्राम खम्हरिया में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही की गई,जिसमें आरोपी रवि सिह बघेल पिता मंगलेश्वर सिह उम्र 18 वर्ष निवासी खम्हरिया 102 को बिक्री करने हेतु घर के बगल के खेत में रखी 10 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 90 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर आरोपी रवि नें अपने साथी अतुल तिवारी व राघवेन्द्र सिंह के साथ मिलकर शराब खरीदने रायपुर कचुलियान जाना व सस्ते रेट पर बिक्री करना बताया। जिससे आरोपियों अतुल तिवारी पिता अशोक तिवारी उम्र 33 वर्ष निवासी नौढिया थाना जमोडी जिला सीधी हाल मुकाम मनगवां बस्ती,राघवेन्द्र सिंह पिता नरेश सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम माड़ौ थाना बैकुण्ठपुर को गिरफ्तार किया है व तस्करी

में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस के मुखबिर सूचना तंत्र व त्वरित कार्यवाही के परिणाम स्वरूप शराब की अवैध तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही में सफलता प्राप्त हुई है। मामले में 90 लीटर देशी शराब, 03 नग मोबाइल व घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन कुल कीमत लगभग 15 लाख रूपये को जप्त किया गया है।

इस कार्यवाई में उप निरीक्षक घनश्याम मिश्र,एसएसपी मनोज बागरी,प्रधान आरक्षी सत्येन्द्र पांडे,अश्वनी शुक्ला,ओमप्रकाश रावत,आरक्षी आशुतोष मिश्रा,राजेश प्रजापति,राहुल पांडे,शशांक यादव व भूपेन्द्र वर्मन की सराहनीय भूमिका रही।

हर घर में शिक्षा का दीप जले, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

» सांदीपनी विद्यालय सागर में आयोजित प्रवेश उत्सव में हुए शामिल » मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित

साधना एक्सप्रेस भोपाल

सागर | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हर घर में शिक्षा का दीप जलना चाहिए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। मंत्री श्री राजपूत सागर स्थित सांदीपनी विद्यालय (महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय) में आयोजित प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रवेश उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति जागरूकता, नए सपनों की शुरुआत और उज्ज्वल भविष्य की ओर पहला कदम है। जब कोई बच्चा पहली बार विद्यालय की दहलीज पर कदम रखता है, तो वह केवल स्कूल में प्रवेश नहीं करता बल्कि ज्ञान, संस्कार और आत्मनिर्भरता की दुनिया में प्रवेश करता है।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रवेश उत्सव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा विद्यालय से जुड़े, शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन को सफल बनाए। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से शिक्षा से दूर रह जाते हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हर घर का हर बच्चा स्कूल जाए और अपने सपनों को पूरा करे।

मंत्री श्री राजपूत ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि आज की शिक्षा ही कल के सशक्त भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनके तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप सहित विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। मंत्री श्री राजपूत ने मेधावी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और छात्राएं उपस्थित रहीं।

मंदिर,स्कूल व आवासीय क्षेत्र के बीच शराब ठेका खोलने का विरोध, ग्रामीणों ने पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल से लगाई मदद की गुहार

साधना एक्सप्रेस नरसिंहपुर

ग्राम करकबेल के ग्रामीणों ने गांव के दुर्गा चौराहा पर प्रस्तावित शराब ठेका खोले जाने के विरोध में पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए ठेके को तत्काल निरस्त कराने की मांग करते हुए बताया कि प्रस्तावित स्थान पूरी तरह से धार्मिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

ज्ञापन में बताया गया कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोली जा रही है, वहां से मंदिर की दूरी लगभग 100 मीटर है जबकि शासकीय स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र भी करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नियमानुसार किसी भी शराब ठेके को धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम 300 मीटर दूर स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यहां इस नियम की अनदेखी की जा रही है।

ग्रामीणों ने आशंका जताई कि ठेका खुलने से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। विशेष रूप से महिलाओं के मंदिर आने-जाने और बच्चों के बाहर खेलने में असुरक्षा का माहौल बन सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह ठेका राजेश उर्फ राजू वेण्णन के निवास स्थान पर खोला जा रहा है, जो चारों ओर से निर्धारित दूरी मानकों का उल्लंघन करता है।

पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया उक्त जानकारी देते हुए विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि ग्रामीणों ने मांग की है कि नियमों का पालन करते हुए इस प्रस्तावित शराब ठेके को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए,ताकि गांव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण सुरक्षित रह सके।

मनगवां में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण महाभियान शुरू

पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का दिया गया मंत्र

साधना एक्सप्रेस मनगवां, रीवा।

भारतीय जनता पार्टी के "प्रशिक्षण महाभियान 2026" के अंतर्गत मनगवां मंडल विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय प्रवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र के सभी पांचों मंडलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में मनगवां मुख्यालय स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के सभा कक्ष में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र प्रजापति रहे।

प्रशिक्षण महाभियान के प्रथम दिवस के पहले सत्र में 102 भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पंजीयन कर प्रशिक्षण में भाग लिया। करीब दो घंटे चले प्रशिक्षण सत्र में संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा गुटबाजी व आपसी विवादों को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही पार्टी की विचारधारा एवं कार्यशैली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य केडी शुक्ला, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुणेंद्र मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि जगजीवन लाल तिवारी, पूर्व विधायक श्रीमती पन्ना बाई प्रजापति, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश प्रजापति, महेंद्र तिवारी, आशा तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष बुटला बंसल, कमलेश बांसल, महेंद्र पटेल, श्याम किशोर पांडे, योगेंद्र दुबे, जगत नारायण मिश्रा, जनपद पंचायत गंगेव अध्यक्ष विकास तिवारी, अंकुश गुप्ता, भाजपा आईटी सेल प्रभारी लवकुश गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, पार्षद राजेंद्र जोगी, पूर्व पार्षद विनोद नामदेव, सुनीता गुप्ता, पप्पू साकेत सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भोपाल में आज से 'शेर-ए पंजाब' फूड फेस्टिवल की शुरुआत

5 अप्रैल तक मिलेगा पारंपरिक पंजाबी व्यंजनों का स्वाद

साधना एक्सप्रेस भोपाल

में आज से 'शेर-ए पंजाबः ए पंजाबी फूड फेस्टिवल' का आगाज़ हो गया है। यह फेस्टिवल 1 से 5 अप्रैल 2026 तक सफल रिट्रीट में आयोजित किया जा रहा है, जहां शहरवासी पंजाब के पारंपरिक स्वाद और संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे।

पांच दिवसीय इस फेस्टिवल में सरसों का साग, मक्के की रोटी, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, अमृतसरी फिश, दाल मखनी, छोले-भटूरे, पनीर टिक्का और राजमा चावल जैसे लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं।

मिठाइयों में लस्सी, फालूदा और गुलाब जामुन खास आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही लाइव तंदूर और स्ट्रीट फूड काउंटर भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फेस्टिवल के शेफ नरेंद्र राजपूत के अनुसार, सभी व्यंजन पारंपरिक पंजाबी शैली में देसी मसालों और मूल रेसिपी के साथ तैयार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पंजाब के असली स्वाद का अनुभव मिल सके। खाने के साथ-साथ फेस्टिवल में पंजाबी लोक संगीत, रंग-बिरंगी सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जो हर आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजकों का कहना है कि यह फेस्टिवल पंजाब की समृद्ध संस्कृति और खानपान को करीब से जानने का बेहतरीन अवसर है।

गर्मी के मौसम में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी नपा अध्यक्ष सुशीला ममार

» नगर पालिका करेली ने शुरू किए निःशुल्क प्याऊ

» शहर के 14 प्रमुख स्थानों पर मिलेगी शीतल पेयजल सुविधा, गर्मी में राहगीरों को राहत

साधना एक्सप्रेस नरसिंहपुर
करेली आशीष नेमा

करेली। भीषण गर्मी में आमजन और राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद करेली nc शहर में निःशुल्क प्याऊ सेवा का शुभारंभ किया है। बुधवार को नगर पालिका द्वारा शहर के 14 प्रमुख स्थानों पर प्याऊ शुरू किए गए, जहां पूरे ग्रीष्मकाल के दौरान लोगों को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

नगर पालिका परिषद द्वारा इस वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने, पुलिस थाना के सामने, शासकीय अस्पताल परिसर के अंदर, बरमान चौराहा सहित शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए हैं। इन स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे बाजार आने वाले नागरिकों, मरीजों के परिजनों तथा राहगीरों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार ने कहा कि गर्मी के मौसम में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था से शहरवासियों के साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीकांत पाटर ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जनसुविधा से जुड़े कार्य लगातार किए जा रहे हैं और प्याऊ व्यवस्था भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे गर्मी के पूरे सीजन में लोगों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्याऊ शुभारंभ के अवसर पर नगर पालिका के पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगरवासियों ने नगर पालिका की इस पहल की सराहना करते हुए इसे गर्मी के मौसम में अत्यंत उपयोगी बताया।

प्रवेश उत्सव में बच्चों को मिलीं निःशुल्क पुस्तकें, नए सत्र 2026-27 का उत्साहपूर्ण आगाज़

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

राजेश नीरस. नवीन शिक्षण सत्र 2026-27 के शुभारंभ के अवसर पर विकासखंड चीचली के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चीचली में विकासखंड स्तरीय प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया।इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया। पुस्तकें प्राप्त कर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य मोना कौरव, मंडल अध्यक्ष नरेश कौरव, केएल साहू, चंद्रकांत गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने मार्गदर्शी उद्बोधन में कहा कि शासन द्वारा संचालित प्रवेश उत्सव की पहल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और उनकी पढ़ाई में सहयोग करें। विद्यालय के प्राचार्य भूपेश ठाकुर ने विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक डीके पटेल ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं लक्ष्य निर्धारण के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ किया। अंत में आभार प्रदर्शन विकासखंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र राजपूत द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक विनीत नामदेव एवं सत्यम ताम्रकार द्वारा किया गया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490, प्रबंध संपादक आशीष नेमा मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698